आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

140

जी. एस. संधवालिया और लपिता बनर्जी से पहले, जे. जे.

आई. एम. टी. औद्योगिक संघ और एक और -

याचिकाकर्ता बनाम

हरियाणा राज्य और एक अन्य उत्तरदाता (ओं) सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 2021 की 26573,24967,25037,25539 और 25988, सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 2022 की 584,1404,3860 और 1698 (ओ एंड एम)

17 नवंबर, 2023

सिविल रिट याचिका-भारत का संविधान, 1950-कला। 14, 19 और 35-हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम, 2020 के अधिकारों को असंवैधानिक और भारत के संविधान के भाग-3 के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी गई-निजी रोजगार में हरियाणा में अधिवासी व्यक्तियों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले अधिनियम को अनुचित, मनमाना, मनमौजी, अत्यधिक, अनावश्यक और राज्य सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान किए गए निजी नियोक्ताओं के व्यापार और व्यापार करने के मौलिक अधिकारों में अत्यधिक घुसपैठ करना-अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के लिए भी तर्क दिया क्योंकि यह भारत के सभी नागरिकों द्वारा हरियाणा में समान रोजगार और रहने और बसने के अधिकार के खिलाफ है। रखरखाव योग्य व्यक्ति के संघ द्वारा याचिका-केवल संसद अनुच्छेद 16 (3) के तहत कानून बना सकती है-बुनियादी संरचना सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है-निजी वादी को वह करने के लिए नहीं कहा जा सकता है जो राज्य नहीं कर सकता है-लगाए गए प्रतिबंध अनुचित हैं-2020 का अधिनियम असंवैधानिक और भाग III का उल्लंघन है-इस प्रकार अप्रभावी-याचिका की अनुमति है।

 क्या रिट याचिका इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचारणीय होगी कि अधिनियम को मुख्य रूप से व्यक्तियों के संघ द्वारा चुनौती दी गई है और क्या वे भारत के संविधान के भाग-3 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा कर सकते हैं और क्या वे गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए उत्तरदायी हैं?

यह अभिनिर्धारित किया गया कि वर्तमान मामलों के समूह में, अधिनियम के अधिकारों को चुनौती देने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर एक सी. डब्ल्यू. पी.-1698-2022 में नोटिस जारी किया गया है और रोक दी गई है, जो यह दर्शाता है कि इस मुद्दे को न केवल व्यक्तियों के संघ द्वारा बल्कि व्यक्तियों द्वारा भी चुनौती दी जा रही है और यह कि आई. एम. टी. औद्योगिक संघ और अन्य बनाम राज्य के गुण-दोष पर निर्णय लेना न्यायालय का बाध्य कर्तव्य है।

141

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिकता-यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के बाद के निर्णयों ने रखरखाव के मुद्दे को स्पष्ट किया है और यह आपत्ति उठाना राज्य का काम नहीं है कि व्यक्तियों का संघ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता है-याचिकाएं जिन्हें बनाए रखा जा सकता है। (पैरा 23,24 और 28)

 क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 35 के तहत प्रदान की गई विशिष्ट बाधा को देखते हुए इस मुद्दे पर कानून बनाना राज्य के दायरे में था और क्या यह कानून प्रविष्टि संख्या के तहत आएगा। संघ सूची का 81?

राज्य द्वारा यह बचाव किया गया कि अधिनियम का उद्देश्य केवल हरियाणा के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता और आजीविका को बढ़ाना और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना और स्थानीय कार्यबल को प्रशिक्षित करना है जो आम जनता के हित में होगा-यह भी प्रस्तुत किया गया कि यह एक उचित प्रतिबंध था जो अनुच्छेद 19 (5) और 19 (6) के तहत अनुमेय था जो आम जनता के हित में था-आगे प्रस्तुत किया गया कि अनुच्छेद 15 (4) के प्रावधान के तहत, राज्य के लिए नागरिक के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति है, हालांकि जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषिद्ध था-केवल इसलिए कि वहाँ कुछ प्रावधान हैं। यदि उद्देश्यों और कारणों में 'प्रवास' शब्द का उपयोग किया गया था, तो सूची I (संघ सूची) की प्रविष्टि 81 का संदर्भ उचित नहीं था। -यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य के विधानमंडल के लिए अनुच्छेद 16 (3) के तहत मामलों के संबंध में कोई कानून नहीं बनाने के लिए एक विशिष्ट प्रतिबंध है, जिसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता होनी चाहिए-16 (3) के तहत दी गई शक्ति केवल संसद को सरकार या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के तहत किसी पद पर रोजगार या नियुक्ति के वर्ग या वर्गों के संबंध में निर्धारित कोई कानून बनाने के लिए दी गई है, जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास की आवश्यकता के अधीन है, बशर्ते कि ऐसी नियुक्ति या नियुक्ति से पहले उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास की आवश्यकता हो-राज्य की रक्षा। यह तर्क देते हुए कि यह भाग-III के लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा था, इस बात को सही ढंग से उजागर किया गया कि भाग-III में दी गई गारंटी को बुनियादी संरचना को नष्ट करके नष्ट नहीं किया जा सकता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता के परस्पर जुड़े खंडों को आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा के भाग-IV में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भाग-III के तहत दिए गए अर्थों की कीमत पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

2024(1)

142

भारत का संविधान-अनुच्छेद 19 (1) (डी) इस हद तक मान्यता देता है कि कोई राज्य बाधा नहीं हो सकती है, केवल इस तथ्य के कारण कि यह प्रांतवाद के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगा-अनुच्छेद 1 और 5 साबित करते हैं कि भारत एक अभिन्न संपूर्ण और एक अविनाशी इकाई है जो प्रशासन की सुविधा के लिए राज्यों में विभाजित है और संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह किसी भी दोहरी नागरिकता के बिना एक उद्देश्य और एकल साम्राज्य के तहत रहने वाले लोगों के देश के रूप में सन्निहित है-याचिकाकर्ताओं का तर्क कि यह कानून का सार और सार है जिसे स्वीकार किया जाना है-यह देखा गया है कि अंतर्निहित उद्देश्य यदि केवल कानून ही है भारत के नागरिकों के बीच एक कृत्रिम अंतर और भेदभाव पैदा करने के लिए और स्वयं कानून बनाने का उद्देश्य इस तथ्य पर आधारित है कि बड़ी संख्या में प्रवासी हैं जो स्थानीय उम्मीदवारों की नौकरी कर रहे हैं जो तुलनात्मक रूप से कम वेतन वाले हैं-इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रवास का मुद्दा प्रविष्टि संख्या के तहत आता है। संघ सूची-प्रश्न की धारा 81 ने राज्य के खिलाफ निर्णय लिया कि इस मुद्दे पर कानून बनाना और निजी नियोक्ता को कर्मचारियों की श्रेणी के लिए खुले बाजार से भर्ती करने से रोकना राज्य के दायरे से बाहर है।

(पैरा 29,30,31,32,35,37,38,39,40 और 48)

 क्या राज्य निजी नियोक्ताओं को ऐसा करने के लिए एक कानून प्रदान कर सकता है जो भारत के संविधान के तहत करने के लिए वर्जित था?

यह अभिनिर्धारित किया गया कि हरियाणा के गैर-निवासियों, जिन्हें द्वितीयक नागरिक के रूप में नहीं माना जा सकता था, उन पर आंखें मूंद लेते हुए भारत के संविधान के मूलभूत वादों के खिलाफ कानून के माध्यम से एक विधायी आदेश लागू नहीं किया जा सकता था-राज्य दूरदर्शी दृष्टि से काम कर रहा था और इस तरह का क़ानून सर्वोच्च न्यायालय और स्वयं संविधान के संवैधानिक निर्णयों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों की अवहेलना करने के लिए उत्तरदायी है-हरियाणा राज्य से संबंधित नागरिकों के एक समूह को द्वितीयक दर्जा शुरू करके संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा का खुले तौर पर उल्लंघन किया गया है-एक विधायी के माध्यम से निजी रोजगार पर प्रतिबंध का दोहन। राज्यों को उक्त प्रतिबंधों से बाहर रखते हुए और उनके उल्लंघन के कारण नियोक्ता को अपराधीकरण के दायरे में रखते हुए आदेश को असंवैधानिक कहा जा सकता है क्योंकि निजी व्यक्ति को वह करने के लिए नहीं कहा जा सकता है जो राज्य को अपने लिए वर्जित किया गया है-राज्य निजी नियोक्ताओं को आई. एम. टी. औद्योगिक संगठन और अन्य बनाम राज्य के लिए निर्देशित नहीं कर सकता है।

143

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

भारत के संविधान के तहत जो करने के लिए मना किया गया है, वह करें।

(पैरा 59,60,64 और 65)

 क्या यह विधान आम जनता के हित में उचित प्रतिबंध प्रदान करता है और इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (5) और 19 (6) के तहत राज्य को इसे उचित ठहराने का अधिकार देता है?

माना जाता है कि पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने या भारत के किसी भी हिस्से या क्षेत्र में रहने और बसने के अधिकार के संबंध में अनुचित प्रतिबंध लगाने वाले उस अधिनियम को किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता है जैसा कि नियोक्ताओं को संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने का निर्देश दे रहा था-अनुच्छेद 2 (ई) के तहत परिभाषित सभी प्रकार के निजी नियोक्ताओं पर लगाए गए प्रतिबंध इस हद तक सकल हैं कि किसी व्यक्ति का व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार अनुच्छेद 19 (1) (जी)-बार के तहत किसी भी अदालत में अधिकृत अधिकारी या नामित अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को चुनौती देने में सक्षम नहीं होने की धारा 20 के तहत घोर रूप से बाधित है। राज्य एक निजी नियोक्ता पर पूर्ण नियंत्रण का प्रयोग करना जारी रखता है-तिमाही रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता, रिकॉर्ड के लिए बुलाने और रिकॉर्ड, रजिस्टर और दस्तावेजों की जांच के लिए केवल एक दिन का नोटिस देकर परिसर का निरीक्षण करने की अधिकृत अधिकारी की शक्ति को 'इंस्पेक्टर राज' कहा जा सकता है-क़ानून में लगाए गए प्रतिबंध दूरगामी प्रभाव रखते हैं और इन्हें किसी भी तरह से उचित नहीं माना जा सकता है जो किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है।

(पैरा 71,73 और 74)

लेखन याचिकाओं की अनुमति दी गई।

याचिकाकर्ता की ओर से सिद्धार्थ डायस और गुरशेर भंडेल, अधिवक्ता (सीडब्ल्यूपी-584-2022 में)। कोई नहीं, याचिकाकर्ताओं के लिए (आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा के सी. डब्ल्यू. पी.-25037,25539 और 25988 में)

2024(1)

144

पुनीत बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता, जगबीर मलिक के साथ, अतिरिक्त अधिवक्ता। प्रतिवादी-राज्य की ओर से ए. जी., हरियाणा, शिवम शर्मा और उदय अग्निहोत्री, अधिवक्ता। यू. ओ. आई. की ओर से धीरज जैन और वरिष्ठ पैनल वकील गुरमीत कौर गिल के साथ भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन।

(2) याचिकाकर्ता संघ को हरियाणा पंजीकरण और समितियों के विनियमन अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के तहत विधिवत पंजीकृत बताया गया है, जिसमें औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, तहसील मानेसर, जिला गुरुग्राम में औद्योगिक भूखंडों/स्थलों के आवंटी शामिल हैं जो हरियाणा राज्य में अपनी औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को चला रहे हैं। अधिकृत प्रतिनिधियों के पक्ष में प्रस्तावों को विधिवत जोड़ा गया है। (3) याचिकाकर्ता '2020 अधिनियम' को इस तथ्य के कारण चुनौती देते हैं कि यह निजी रोजगार में आरक्षण प्रदान करता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान किए गए अपने व्यवसाय और व्यापार को जारी रखने के लिए निजी नियोक्ताओं के मौलिक अधिकारों में राज्य सरकार द्वारा एक अभूतपूर्व घुसपैठ पैदा करता है। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं के अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों को उचित नहीं माना जाता है और वे स्पष्ट रूप से मनमाने, मनमौजी, अत्यधिक और अनावश्यक हैं और वही भारत के संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित प्राकृतिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और चुनौती के अधीन हैं। इसी तरह, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का भी उतना ही आरोप लगाया जाता है जितना कि देश के सभी नागरिकों को आई. एम. टी. औद्योगिक संघ का अधिकार होगा और एक अन्य बनाम भारत के संविधान का राज्य।

145

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

हरियाणा राज्य की दलीलें (4) अपने जवाब में राज्य का रुख यह था कि याचिकाकर्ता-संघ के सदस्यों को उनका व्यवसाय और व्यापार करने के लिए रियायती दरों पर औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए थे और इसलिए, आवंटन में एक पूर्व शर्त थी कि 75 प्रतिशत रोजगार हरियाणा के अधिवासी व्यक्तियों को दिया जाना था, जहां पद तकनीकी प्रकृति के नहीं हैं। एच. एस. आई. आई. डी. सी. की वर्ष 2005 और 2011 की नीतियों में ऐसी पूर्व शर्त प्रदान की गई थी जिसे आवंटन के संबंधित नियमित पत्र के साथ जोड़ा गया था और इसलिए, यह कहा गया था कि रिट याचिका में भौतिक तथ्यों का दमन और छिपाना था। याचिकाकर्ताओं के संवैधानिक न्यायालयों के अनुच्छेद 226 या 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के अधिकार पर आपत्ति जताई गई थी और यह कि संघ अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता था। क़ानून को इस आधार पर उचित ठहराया गया था कि इसने अधिवास के आधार पर एक उचित वर्गीकरण किया था, जो अनुमत था और भौगोलिक सीमाओं के आधार पर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता था। इस कानून के उद्देश्यों और कारणों पर प्रकाश डाला गया और औद्योगिक शक्ति घरानों पर प्रवासी मानव संसाधनों के साथ एक असमान सौदे को लागू करके और वेतन के लिए बेंचमार्क को कम करके अपनी प्रमुख स्थिति का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया। भारत के संविधान की (राज्य सूची) सूची II की प्रविष्टि 24 और प्रविष्टि 27 के साथ-साथ सूची III (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 24 और प्रविष्टि 36 पर यह निर्धारित करने के लिए भरोसा किया गया था कि निजी नियोक्ता हरियाणा राज्य में स्थानीय लोगों को नौकरी प्रदान करने की पेशकश नहीं कर रहे थे या करने में अनिच्छुक थे। यह स्थानीय आबादी की बेरोजगारी का यह पहलू था जिसे प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किया जाना था। वर्गीकरण को कथित तौर पर व्यक्तियों या चीजों को अलग करने वाले समझदार अंतर पर आधारित किया गया था जो आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा हैं।

2024(1)

146

एक साथ समूहीकृत किया गया और कहा गया कि प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध है। (5) यह माना गया कि निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के अधिकार को किसी भी तरह से प्रतिबंधित किया जा सकता है, विशेष रूप से क्योंकि यह केवल कम वेतन वाली नौकरियों के लिए रोजगार के संबंध में था, न कि अन्य उच्च कुशल/विशेषज्ञ/प्रबंधकीय या अन्य तकनीकी रूप से अच्छी नौकरियों के लिए। हरियाणा की अधिकांश कृषि भूमि को कृषि गतिविधियों के अलावा विभिन्न उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित/समेकित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कृषि आधारित समाज में बेरोजगारी पैदा हो गई थी। तदनुसार यह न्यायसंगत था कि यह अधिनियम केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले किसी अन्य संगठन के तहत सार्वजनिक रोजगार के संबंध में भेदभाव नहीं करता था और भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों वाले भारत के संविधान के अध्याय III के प्रतिकूल नहीं था। यह अनुरोध किया गया था कि जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण भारत के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, लेकिन अधिवास के आधार पर रोजगार भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (1) का उल्लंघन नहीं करेगा और बेरोजगार स्थानीय युवा एक अलग वर्ग हैं और इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद नए रोजगार में निजी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से इस विशेष वर्ग का उचित वर्गीकरण किया जा सकता है। तदनुसार, यह अनुरोध किया गया था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 वर्ग कानून को मना करता है लेकिन उचित वर्गीकरण को मना नहीं करता है। परिणामस्वरूप, यह अंतर करने की कोशिश की गई कि अधिवास और जन्म स्थान कानून और तथ्य दोनों में अलग-अलग अर्थों वाली दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं। आंध्र प्रदेश विधान, जिन अवधारणा से इसे कथित रूप से नकल किया गया था, को इस आधार पर अलग करने की मांग की गई थी और यह अनुरोध किया गया था कि अधिवास आधारित लाभ को मान्यता दी गई थी और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे बरकरार रखा गया था। अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को एक पूर्ण अधिकार नहीं बल्कि एक योग्य अधिकार होने का अनुरोध किया गया था और राज्य आम जनता के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकता है और यह अनुरोध किया गया था कि कम वेतन वाली नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले बड़ी संख्या में प्रवासियों के आने से स्थानीय बुनियादी ढांचे और आवास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है जिससे झुग्गियों का प्रसार हुआ है। इसने पर्यावरण और स्वास्थ्य के मुद्दों को जन्म दिया था जो हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता और रहने की क्षमता को प्रभावित कर रहे थे और इसलिए, कम वेतन वाली नौकरियों के लिए स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा रही थी और ऐसी कोई भी प्राथमिकता आम जनता के हित में थी। कानून के सूर्यास्त खंड पर प्रकाश डाला गया कि अधिनियम 10 वर्षों के बाद प्रभावी नहीं होगा और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य की क्षमता पर प्रकाश डाला गया।

Rs.30,000/- प्रति आई. एम. टी. औद्योगिक संगठन की राशि और अन्य बनाम राज्य

147

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

(6) भारत संघ ने अपने प्रारंभिक संक्षिप्त जवाब में, जो कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों के शामिल होने के कारण जवाब दाखिल करने के लिए 22.02.2022 पर निर्देश जारी किए जाने के बाद दायर किया गया था, यह दलील ली कि कानून राज्य का कानून होने के कारण, केंद्र सरकार की कोई टिप्पणी नहीं थी और मंजूरी हरियाणा के राज्यपाल द्वारा दी गई थी और इसे राज्य का कानून होने के कारण भारत के माननीय राष्ट्रपति को नहीं भेजा गया है। 04.03.2022 पर एक विस्तृत पैरा-वार जवाब दाखिल करने के निर्देश जारी किए जाने के कारण, क्योंकि यह अधिनियम भारत के अन्य नागरिकों को प्रभावित करेगा, जो अधिवासी नहीं हो सकते हैं, श्री द्वारा दिनांकित 08.03.2022 का एक और संक्षिप्त जवाब दाखिल किया गया था। आर. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव और कानूनी सलाहकार, कानूनी मामले विभाग, भारत सरकार। उद्देश्यों और कारणों को फिर से यह बताने के लिए उजागर किया गया कि यह एक उचित सहसंबंध रखने वाला राज्य का कानून था जिसे प्राप्त करने की मांग की गई थी और इस पहलू को स्पष्ट करना राज्य के लिए उचित था न कि भारत संघ के लिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 का संदर्भ यह दलील देने के लिए दिया गया था कि राज्य ने यह स्वीकार किया था कि यह एक राज्य विधान था और इस विषय पर राज्य द्वारा अधिनियमित किया गया था जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टियों 24 और 27 और सूची III (समवर्ती सूची) की प्रविष्टियों 24 और 36 के तहत उसके विधायी अधिकार क्षेत्र में आता है। नतीजतन, कुल मिलाकर, भारत संघ के पास इस स्थिति में होने वाले कानूनी विमर्श पर देने के लिए बहुत कुछ नहीं है। (7) विचाराधीन अधिनियम को 06.11.2021 पर अधिसूचित किया गया था और उक्त अधिनियम की धारा 1 (3) के प्रावधानों को देखते हुए, अधिनियम W. E. F. 15.01.2022 (अनुलग्नक पी-8) से लागू हुआ। जाहिरा तौर पर, राज्य ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अध्यादेश, 2020 (अनुलग्नक पी-4) पेश किया, जिसमें हरियाणा राज्य में एक नियोक्ता द्वारा स्थानीय उम्मीदवारों को 75 प्रतिशत रोजगार प्रदान करने की मांग की गई थी। कहा जाता है कि आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा पर विधेयक को पेश करने के लिए अभ्यावेदन के रूप में राज्य भर में आपत्तियां उठाई गई थीं।

2024(1)

148

31.10.2020 अर्थात् हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार विधेयक, 2020 (अनुलग्नक पी-5) जिसमें उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि कम वेतन वाली नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले बड़ी संख्या में प्रवासियों की आमद थी जो स्थानीय बुनियादी ढांचे और आवास को प्रभावित कर रही है और अंततः झुग्गियों के प्रसार की ओर ले जा रही है। जीवन और आजीविका की गुणवत्ता प्रभावित हुई है और इसलिए, कम वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने की मांग की जाती है क्योंकि यह सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के लिए वांछनीय था और ऐसी प्राथमिकता आम जनता के हित में होगी। इसी तरह, इस तथ्य पर जोर दिया गया कि यह निजी नियोक्ताओं को स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करेगा और उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योग्य और प्रशिक्षित स्थानीय कार्यबल का लाभ मिलेगा और बड़े पैमाने पर उद्योग की दक्षता में वृद्धि होगी क्योंकि कार्यबल किसी भी औद्योगिक संगठन/कारखाने के विकास के लिए प्रमुख घटकों में से एक है। विधेयक की मुख्य विशेषताओं में से एक यह थी कि योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जहां योग्य या उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं। विचाराधीन अधिनियम को लागू करने के उद्देश्य और कारण इस प्रकार हैंः -

“हरियाणा सरकार। जीएजेड। (अतिरिक्त)। अक्टूबर. 31,2020

(के. आर. टी. के. 9,1942 साका)

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

हरियाणा स्थानीय उम्मीदवारों का राज्य रोजगार विधेयक, 2020 " कम वेतन वाली नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले बड़ी संख्या में प्रवासियों की आमद स्थानीय बुनियादी ढांचे और आवास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है और झुग्गियों के प्रसार की ओर ले जाती है जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य के मुद्दे पैदा हुए हैं जो हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता और आजीविका को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए, कम वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों को वरीयता देना सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से वांछनीय है और ऐसी कोई भी प्राथमिकता आम जनता के हित में होगी। वर्तमान विधेयक के अधिनियमन के साथ, बड़े पैमाने पर जनता के हित में, राज्य सभी आई. एम. टी. औद्योगिक संघ और अन्य बनाम राज्य को भी प्रोत्साहित करने जा रहा है।

149

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

बी। योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करना जहां योग्य या उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए विधेयक।

दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री, हयाना

चंडीगढ़ः 31 अक्टूबर, 2020

आर. के. नंदल, सचिव। ” (8) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान, जो स्पष्ट रूप से हमारे विचार में हैं, धारा 2 (ई) के तहत "नियोक्ता" की परिभाषा होगी जिसमें कोई कंपनी या कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सेवा के निर्माण या प्रदान करने के उद्देश्यों के लिए वेतन/मजदूरी आदि पर 10 या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करता है, वह दायरे में आएगा, लेकिन अपवर्जन खंड यह था कि इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाला कोई भी संगठन शामिल नहीं होगा। धारा 2 (जी) के तहत, "स्थानीय उम्मीदवार" की परिभाषा है अर्थात वह जो हरियाणा राज्य में अधिवासित था और स्पष्ट संदर्भ निवास के लिए होगा, हालांकि इसका उल्लेख अधिनियम में ही नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों में अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान है, जिसमें आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा के लागू होने के तीन महीने के भीतर सकल मासिक वेतन या 1,000/- से अधिक वेतन अर्जित करने वाले या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए कर्मचारियों को निर्दिष्ट पोर्टल पर पंजीकृत किया जाना था।

2024(1)

150

अधिनियम और प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी नियोक्ता द्वारा नियुक्त या नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे सभी कर्मचारियों का पंजीकरण निर्दिष्ट पोर्टल पर पूरा नहीं हो जाता है। Rs.50,000/- की इस राशि को 06.01.2021 की अधिसूचना द्वारा घटाकर Rs.30,000/- कर दिया गया था, जो उस सम तिथि की थी जब अधिनियम W. E. F. 15.01.2022 लागू होने वाला था। संबंधित प्रावधान इस प्रकार हैंः -

“भाग-I हरियाणा सरकार

कानून और विधायी विभाग

अधिसूचना

2 मार्च, 2021

(4) अपने प्रारंभ की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति पर इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, सिवाय उन कार्यों के जो ऐसे उपकरकर्ता के समक्ष किए जाने हैं या किए जाने से छूट गए हैं और ऐसे उपकरदाता पर सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का केंद्रीय अधिनियम 10) की धारा 6 लागू होगी। लागू होगा जैसे कि यह अधिनियम तब किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा निरसित किया गया था, जैसा भी मामला हो। (5) यह अधिनियम सभी कंपनियों, निगमों, न्यासों पर लागू होता है। सीमित देयता।

साझेदारी फर्म, साझेदारी फर्म और आई. एम. टी. औद्योगिक संगठन और अन्य बनाम राज्य

151

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी नियोक्ता द्वारा तब तक नियुक्त या नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे सभी कर्मचारियों का पंजीकरण निर्दिष्ट पोर्टल पर पूरा नहीं हो जाता है। स्पष्टीकरण। इस अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के प्रयोजन के लिए, निर्दिष्ट पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया सरकार, आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा द्वारा अधिसूचित नियमों के तहत निर्धारित की जाएगी।

2024(1)

152

समय-समय पर। ”

(9) अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान किया गया है कि नियोक्ता को ऐसे पदों के संबंध में 75 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त करना था, जहां सकल मासिक वेतन या मजदूरी उक्त राशि रु। 50, 000/-, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था, Rs.30,000/- में विधिवत संशोधन किया गया था। परंतुक में आगे यह प्रावधान किया गया है कि स्थानीय उम्मीदवार राज्य के किसी भी जिले से हो सकते हैं, लेकिन नियोक्ता को किसी भी जिले के स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार को स्थानीय उम्मीदवारों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत तक सीमित करने का अधिकार था और स्थानीय उम्मीदवार अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए तभी पात्र होंगे जब वह निर्दिष्ट पोर्टल के तहत खुद को पंजीकृत करेगा। डब्ल्यू. ई. एफ. 15.01.2022 अधिनियम को लागू करने वाली अधिसूचनाएँ और पंजीकरण के लिए सकल मासिक वेतन या मजदूरी के रूप में Rs.30,000/- को अधिसूचित करना इस प्रकार हैः -

“ हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

6 नवंबर, 2021

डॉ. राजा शेखर वुंदरु, हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्रम विभाग। ”

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

6 नवंबर, 2021

नहीं। Lab./25478/2021। - हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम, 2020 (2021 का 3) की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल एतद्द्वारा पंजीकरण के लिए सकल मासिक वेतन या मजदूरी के रूप में तीस हजार रुपये को अधिसूचित करते हैं। यह अधिसूचना 15 जनवरी, 2022 यानी उक्त अधिनियम के लागू होने की तारीख से लागू होगी।

आई. एम. टी. औद्योगिक संघ और एक अन्य बनाम राज्य

153

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

डॉ. राजा शेखर वुंदरु, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग। (10) नियोक्ता को छूट का अधिकार दिया गया था जहां वांछित कौशल, योग्यता या प्रवीणता के पर्याप्त संख्या में स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे और नामित अधिकारी को ऐसे प्रपत्र और तरीके से आवेदन किया जाना था जो अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्धारित किया जा सके। अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) में प्रावधान किया गया है कि नामित अधिकारी स्थानीय उम्मीदवारों की भर्ती के लिए नियोक्ता द्वारा किए गए प्रयास का मूल्यांकन करने के बाद जांच करें और फिर या तो छूट के लिए उनके दावे को स्वीकार करें या लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए इसे अस्वीकार कर दें और अंत में नियोक्ता को वांछित कौशल, योग्यता और दक्षता प्राप्त करने के लिए स्थानीय उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने का निर्देश दें। नामित अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों को सरकार की वेबसाइट पर रखा जाना था और अधिनियम की धारा 6 के तहत, निर्दिष्ट पोर्टल पर तिमाही के दौरान उल्लिखित और नियुक्त स्थानीय उम्मीदवारों की संख्या के बारे में सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली तारीख तक नियोक्ता द्वारा पोर्टल रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी। अधिनियम की धारा 7 के तहत अभिलेख मंगाने और अधिनियम की धारा 6 के तहत नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को छूट देने के लिए अधिकृत अधिकारी की शक्ति प्रदान की गई है, जिन्हें अधिनियम के उद्देश्यों का पालन करने के लिए आगे कोई भी आदेश पारित करना था और उक्त आदेश को सरकार की वेबसाइट पर रखा जाना था। धारा 8 ने अधिकृत अधिकारी को अधिनियम के तहत उसे सौंपे गए किसी भी कार्य को करने के उद्देश्यों के लिए और किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित करने के लिए और क्या अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन किया गया है और क्या उसे रिकॉर्ड, रजिस्टर और दस्तावेजों की जांच करने का अधिकार दिया है यदि उसे यह विश्वास करने का कारण था कि अधिनियम या नियमों के तहत कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है। प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः -

“4. इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद, प्रत्येक नियोक्ता ऐसे पदों के संबंध में पचहत्तर प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त करेगा जहां सकल मासिक वेतन या मजदूरी 13 या पचास हजार रुपये से अधिक या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित नहीं हैः बशर्ते कि स्थानीय उम्मीदवार राज्य के किसी भी जिले से हो सकते हैं, लेकिन नियोक्ता अपने विकल्प पर किसी भी जिले के स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार को दस आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा तक सीमित कर सकता है।

2024(1)

154

(2) अधिकृत अधिकारी के पास धारा 6 के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट को सत्यापित करने के उद्देश्यों के लिए किसी भी नियोक्ता के कब्जे में किसी भी रिकॉर्ड, जानकारी या दस्तावेज को मंगाने की शक्तियां होंगी। (3) प्राधिकृत अधिकारी, रिपोर्ट की जांच के बाद, इस अधिनियम के उद्देश्यों का पालन करने के लिए कोई भी आदेश पारित कर सकता है, जो आवश्यक हो।

आई. एम. टी. औद्योगिक संघ और एक अन्य बनाम राज्य

155

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

(3) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के तहत अधिकृत अधिकारी को उसके कार्यों के निष्पादन में जानबूझकर देरी या बाधा डालता है, तो वह इस अधिनियम के तहत अपराध का दोषी होगाः बशर्ते कि 6 बजे के बीच के अलावा कोई प्रवेश नहीं किया जाएगाः 00 और 18: 00 और प्रवेश करने के इरादे की सूचना उस तारीख से कम से कम एक दिन पहले दी जाती है जिस दिन प्रवेश करने का प्रस्ताव है। ”

(11) नियोक्ता को कानूनी दायित्व के तहत होने के कारण अधिकृत अधिकारी को सहायता प्रदान करनी होती थी या यदि वह अधिनियम की धारा 8 (2) के तहत बिना किसी उचित कारण के ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे अपराध का दोषी ठहराया जा सकता है और इसी तरह यदि वह अपने कार्यों के प्रदर्शन में अधिकृत अधिकारी को देरी या बाधा डालने का प्रयास करता है, तो उसे धारा 8 (3) के तहत अपराध का दोषी ठहराया जा सकता है। परंतुक में प्रावधान किया गया था कि प्रवेश को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के भीतर प्रतिबंधित किया जा सकता है और इरादे की सूचना उस तारीख से कम से कम एक दिन पहले दी जानी थी जिस दिन प्रवेश करने का प्रस्ताव किया गया था। आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा द्वारा पारित आदेशों के संबंध में धारा 9 के तहत अपील का अधिकार दिया गया है।

2024(1)

156

नामित अधिकारी या अधिकृत अधिकारी 60 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकरण के पास जाता है और उसके साथ ऐसी फीस भी होती है जो निर्धारित की जाए और अपीलीय प्राधिकरण को अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देना होता है और अपील का जल्द से जल्द निपटारा करना होता है, जिससे धारा 9 (4) और 9 (5) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके उसे रद्द करने, पुष्टि करने या संशोधित करने की शक्ति मिलती है। (12) धारा 10 जुर्माने के प्रावधानों का प्रावधान करती है जो Rs.10,000/- से कम नहीं हैं और जो Rs.50,000/- तक बढ़ेंगे और यदि उल्लंघन दोषी ठहराए जाने के बाद भी जारी रहता है, तो प्रत्येक दिन के लिए Rs.100 तक और जुर्माना लगाया जा सकता है जब तक कि उल्लंघन जारी नहीं रहता है। अधिनियम की धारा 11 में प्रावधान है कि यदि निर्दिष्ट पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करने के अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन किया गया था, तो नियोक्ता को किसी ऐसे अपराध का दोषी ठहराया जा सकता है, जिसके लिए जुर्माना Rs.25,000/- से कम नहीं होगा, जो रु. 1,00,000 तक जा सकता है और इसके अलावा यदि उल्लंघन दोषी ठहराए जाने के बाद भी जारी रहता है, तो दंड को प्रत्येक दिन के लिए Rs.500 तक बढ़ाया जा सकता है, जब तक कि उल्लंघन जारी नहीं रहता है। इसी तरह का प्रावधान धारा 12 के तहत धारा 4 के तहत स्थानीय उम्मीदवारों को दर्ज नहीं करने के उल्लंघन के लिए प्रदान किया गया है, जिसमें अधिकतम रुपये के साथ न्यूनतम 1,000/- के जुर्माने का प्रावधान किया गया है-और यदि उल्लंघन दोषी ठहराए जाने के बाद भी जारी रहता है, तो उल्लंघन जारी रहने तक प्रत्येक दिन 1,000/- के निरंतर जुर्माने को बढ़ाया जा सकता है। धारा 5 के तहत पारित आदेश की अवज्ञा के लिए दंड की चौथी श्रेणी धारा 13 के तहत दी गई है, जिसमें छूट का दावा किया गया था, जिसमें Rs.10,000/- से Rs.50,000/- के बीच का अंतर प्रदान किया गया था और जो Rs.100 तक बढ़ सकता है-उल्लंघन जारी रहने तक प्रति दिन जुर्माना जारी रखने के लिए। उक्त प्रावधान इस प्रकार हैंः -

“10. इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किए जाने के अलावा, यदि नियोक्ता द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों या इस अधिनियम के तहत दिए गए किसी लिखित आदेश का कोई उल्लंघन किया जाता है, तो वह एक ऐसे जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो पचास हजार रुपये तक बढ़ सकता है, और यदि उल्लंघन दोषसिद्धि के बाद भी जारी रहता है, तो अतिरिक्त जुर्माने के साथ, जो उल्लंघन जारी रहने तक प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये तक बढ़ सकता है।

आई. एम. टी. औद्योगिक संघ और एक अन्य बनाम राज्य

157

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

12. इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किए जाने के अलावा, यदि कोई नियोक्ता धारा 4 या उसके तहत बनाए गए किसी नियम के प्रावधानों या उसके तहत दिए गए किसी लिखित आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह जुर्माने से दंडनीय अपराध का दोषी होगा जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो दो लाख रुपये तक बढ़ सकता है और यदि उल्लंघन दोषी ठहराए जाने के बाद भी जारी रहता है, तो अतिरिक्त जुर्माने के साथ जो उल्लंघन जारी रहने तक प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपये तक बढ़ सकता है। 13. इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित को छोड़कर, यदि कोई नियोक्ता धारा 5 के तहत नामित अधिकारी द्वारा लिखित रूप में दिए गए किसी आदेश की अवज्ञा करता है, तो वह दंडनीय अपराध का दोषी होगा जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो पचास हजार रुपये तक बढ़ सकता है और यदि उल्लंघन दोषी ठहराए जाने के बाद भी जारी रहता है, तो अतिरिक्त दंड के साथ जो उल्लंघन जारी रहने तक प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये तक बढ़ सकता है। ”

(13) धारा 14 में गलत रिकॉर्ड या जालसाजी पेश करने या जानबूझकर गलत बयान देने या पेश करने या उपयोग करने या गलत विवरण, नोटिस या रिपोर्ट देने या देने के लिए दंड का प्रावधान है, जिसके लिए प्रत्येक अपराध के लिए Rs.50,000/- तक की सजा हो सकती है। उपखंड (2) के तहत, बार-बार अपराध करने वाले के लिए जुर्माना रुपये से कम नहीं होना चाहिए, जो अधिकतम रुपये तक जा सकता है। छूट के संबंध में धारा 5 और रिपोर्ट के संबंध में धारा 7 के तहत दी गई सुनवाई के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल किया गया था, जिन्हें अधिकृत अधिकारी द्वारा छूट दी जानी थी। अपराध करने वाले व्यक्ति का दायित्व, एक कंपनी के लिए, धारा 16 के तहत प्रदान किया गया था कि प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक या प्रबंधन से संबंधित अन्य अधिकारी या व्यक्ति, जब तक कि वह यह साबित नहीं करता है कि आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

158

अपराध उसकी जानकारी या सहमति के बिना किया गया था, ऐसे अपराध का दोषी माना जाए। धारा 17 एक साझेदारी चिंता पर दायित्व प्रदान करती है जो इसे किसी भागीदार या भागीदार या नामित भागीदार या सीमित देयता साझेदारी के भागीदारों की सहमति या मिलीभगत के कारण या भागीदार या भागीदार की ओर से किसी भी उपेक्षा के कारण सीमित करती है। सोसाइटियों या ट्रस्टों के संबंध में, सोसाइटी या ट्रस्ट के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति को अपराध का दोषी माना जाना था और उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी थी और वे केवल तभी उक्त दायित्व से बच सकते थे जब वे यह साबित कर सकें कि अपराध उनकी जानकारी के बिना किया गया था या उन्होंने इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था। सहमति या मिलीभगत या उपेक्षा किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी ठहराने के लिए भी आधार थी, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, तदनुसार दंडित किया जा सकता है और न्यायालय उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर संज्ञान ले सकता है जिस दिन अपराध का कथित कार्य अधिकृत अधिकारी या नामित अधिकारी के संज्ञान में आया था। संबंधित प्रावधान इस प्रकार हैंः -

(15) (1) इस अधिनियम के तहत कोई आदेश धारा 5 या धारा 7 के तहत तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि नियोक्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। (2) इस अधिनियम के तहत कोई जुर्माना तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को नामित अधिकारी द्वारा लिखित रूप में एक नोटिस नहीं दिया जाता है, जिसमें उसे आई. एम. टी. औद्योगिक संघ और अन्य बनाम राज्य के आधारों के बारे में सूचित किया जाता है।

159

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसा अपराध करने से रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था। (2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी सोसायटी या ट्रस्ट द्वारा किया गया है और यह साबित होता है कि अपराध किसी निदेशक, आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

2024(1)

160

प्रबंधक, सचिव, न्यासी या सोसायटी या न्यास के अन्य अधिकारी, ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव, न्यासी या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा। ”

तथ्यात्मक मैट्रिक्स (15) समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से अधिनियम के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी गई थी, यह देखते हुए कि मुख्य मुद्दा यह था कि क्या कोई राज्य अधिवास के आधार पर रोजगार (यहां तक कि निजी क्षेत्र में भी) को प्रतिबंधित कर सकता है। इसके बाद मामले को शीर्ष अदालत में ले जाया गया, जिसमें यह निर्देश दिया गया कि चूंकि चुनौती विधान के लिए थी और बिना किसी कारण के रोक नहीं दी जा सकती थी और परिणामस्वरूप, शीर्ष अदालत ने चार सप्ताह की अवधि के भीतर रिट याचिका पर तेजी से निर्णय लेने का निर्देश दिया। हालाँकि, हरियाणा राज्य को इस तर्क को ध्यान में रखते हुए नियोक्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने का आदेश दिया गया था कि उन्हें भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वे अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से राज्य के बाहर से किसी को भी नियुक्त नहीं कर सकते थे। 22.02.2022 पर यह देखा गया कि भारत संघ अपना जवाब दाखिल नहीं कर रहा था। 04.03.2022 दिनांकित आदेश के माध्यम से, यह देखा गया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा संक्षिप्त उत्तर दायर किया गया था। संबंधित मुद्दे को ध्यान में रखते हुए पैरा वाइज जवाब दाखिल करने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके बाद इस मामले को एक अन्य पीठ के समक्ष रखा गया क्योंकि पीठ के एक सदस्य ने खुद को अलग कर लिया था। समन्वय पीठ ने मार्च 2022 में एक सप्ताह से अधिक समय तक चली दलीलें सुनी थीं और फैसला सुरक्षित रखा गया था। इसके बाद मामले को फिर से 07.09.2022 पर सूचीबद्ध किया गया क्योंकि कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करने की आवश्यकता थी। इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि उसके बाद रोस्टर में बदलाव को देखते हुए विशेष पीठ का गठन करना पड़ा था।

चूंकि न्यायाधीशों में से एक आई. एम. टी. औद्योगिक संघ और एक अन्य बनाम राज्य का राज्य रहा है।

161

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

श्री अनुपम गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता की कानूनी दलीलें (16) याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनुपम गुप्ता ने धारा 16 (2) और 16 (3) के प्रावधानों पर भारी निर्भरता रखते हुए अधिनियम पर हमला करते हुए कहा कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता है और केवल संसद ही किसी भी रोजगार या कार्यालय के वर्ग या वर्गों के अनुसार कोई कानून बना सकती है जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर सरकार या स्थानीय या अन्य प्राधिकरणों के लिए भी प्रतिबंधित था, जो निवास के आधार पर हो सकता है। इसी तरह, भारत के संविधान के अनुच्छेद 35 पर यह प्रस्तुत करने के लिए भरोसा किया गया था कि राज्य के विधानमंडल को अनुच्छेद 16 के खंड 3 के तहत किसी भी अन्य मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्तियां देने से मना किया गया था और यह संसद के एकमात्र अधिकार क्षेत्र में था जिसे निवास के आधार पर कानून में संशोधन करने की एकमात्र विधायी क्षमता थी। परिणामस्वरूप, सूची-I (संघ सूची) की प्रविष्टि No.81 का उल्लेख करते हुए विधायी क्षमता के आधार पर अधिनियम के अधिकारों को चुनौती दी गई, जिसमें नागरिकता, प्राकृतिककरण और विदेशियों से संबंधित प्रविष्टि No.17 के साथ पढ़ने वाले अंतर-राज्यीय प्रवास और अंतर-राज्यीय संगरोध का प्रावधान किया गया था। भारत के क्षेत्र से बाहर स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19 (1) (डी) को उपखंड (ई) के अलावा आवागमन में धकेल दिया गया था, जिसके तहत अनुच्छेद 19 (5) के प्रावधानों की ओर इशारा करते हुए सभी नागरिकों को भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के अधिकार की गारंटी दी गई थी। यह तर्क दिया गया कि राज्य के पास केवल कोई भी कानून बनाने की शक्ति है जिसके द्वारा वह उचित प्रतिबंध लगा सकता है जो आम जनता के हित में या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हित में होगा। अनुच्छेद 19 (6) का संदर्भ दिया गया था कि राज्य की शक्ति केवल आम जनता के हित में कानून बनाने के संबंध में थी, जिसमें अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत प्रदत्त किसी भी पेशे के अभ्यास या किसी भी व्यवसाय को करने से संबंधित अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध होना चाहिए था, जिसका उक्त क़ानून के आधार पर भी उल्लंघन किया जा रहा था। परिणामस्वरूप, यह तर्क दिया गया कि राज्य शिक्षा के लिए अनुमेय अधिवास प्रदान कर सकता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (3) का उल्लेख करते हुए उक्त अधिनियम के प्रावधान राज्य की शक्ति के साथ धोखाधड़ी थे। यह तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 15 (1) और आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा के तहत जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध था।

2024(1)

162

(17) तदनुसार, यह तर्क दिया गया कि यह क्षेत्रीय रूढ़िवाद का मामला था और अनुच्छेद 16 (2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान के भाग-3 के तहत एक स्पष्ट प्रतिबंध था, जो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है और किसी भी नागरिक को जन्म या निवास स्थान के कारण राज्य के तहत किसी भी रोजगार या कार्यालय में अयोग्य या भेदभाव नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत "नागरिकों" की परिभाषा का संदर्भ दिया गया था, जिसमें भारत के क्षेत्र में अधिवासित होने और भारत के क्षेत्र में पैदा होने का प्रावधान किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 1 (1) के अनुसार भारत और राज्यों के संघ की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र शामिल थे। देश की एकता को अलग-अलग हिस्सों में विभाजित करने की मांग वरिष्ठ वकील द्वारा व्यक्त की गई गंभीर चिंता थी और एक अलग राज्य में पैदा होने के आधार पर निजी रोजगार के अधिकार से वंचित किया जा रहा था। (18) तदनुसार, यह तर्क दिया गया कि अधिनियम के तहत अभियोजन के दर्द और संविधान द्वारा राज्य को निषिद्ध करने के लिए निजी नियोक्ता को आदेश नहीं दिया जा सकता है कि राज्य के लिए क्या निषिद्ध था। अनुच्छेद 38 और लोगों के कल्याण की सुरक्षा के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने और आय में असमानताओं को कम करने और स्थिति में असमानताओं को समाप्त करने और अवसर प्रदान करने के लिए राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख करते समय लोगों के एक समूह से अवसरों को वापस लेने और जन्म के आधार पर लोगों के दूसरे समूह को देने के बराबर होगा। उद्देश्यों और कारणों में देश के नागरिकों को प्रवासी के रूप में नामित करने पर वरिष्ठ वकील ने इस आधार पर जोरदार हमला किया कि भाग IVA के अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य जो उप-खंड (ई) के तहत प्रदान किए गए थे, वे देश के लोगों के बीच सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना था, जिन्हें क्षेत्रीय और विभागीय विविधताओं की सीमाओं को पार करना पड़ा। तदनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि अनुच्छेद 19 (1) (डी)

आई. एम. टी. औद्योगिक संघ और एक अन्य बनाम राज्य

163

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

श्री पुनीत बाली, राज्य के वरिष्ठ अधिवक्ता की खंडन प्रस्तुतियाँ (20) राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पुनीत बाली ने प्रारंभिक आपत्ति जताई कि वर्तमान याचिका आई. एम. टी. औद्योगिक संघ और मानेसर औद्योगिक कल्याण संघ और आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा द्वारा दायर की गई है।

2024(1)

164

3 आकाशवाणी 1965 एससी 40

4 2007 (33) आर. सी. आर. (सिविल) 69 आई. एम. टी. औद्योगिक संघ और अन्य बनाम राज्य

165

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न (22) दलीलों और उठाए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि हमारे द्वारा निर्णय के लिए निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होंगेः -

3. यदि प्रश्न संख्या 2 का किसी भी तरह से उत्तर दिया जाता है, तो क्या राज्य निजी नियोक्ताओं को ऐसा करने के लिए एक कानून प्रदान कर सकता है जो भारत के संविधान के तहत करने के लिए उसके लिए वर्जित था? 4. क्या यह विधान आम जनता के हित में उचित प्रतिबंध प्रदान करता है और इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (5) और 19 (6) के तहत राज्य को इसे उचित ठहराने का अधिकार देता है?

Q.No.1 का उत्तर दें

(23) की स्थिरता पर श्री बाली द्वारा उठाए गए तर्क

5 1994 (1) एससीसी 1

6 2007 (8) एस. सी. सी. 449 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

166

(24) अन्यथा भी, यदि आर. सी. कूपर बनाम भारत संघ 7, जिसे अधिक प्रमुखता से बैंक के राष्ट्रीयकरण मामले के रूप में जाना जाता है, में सर्वोच्च न्यायालय की 11-न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित करना है, तो रिट याचिकाओं की रखरखाव के संबंध में उक्त मुद्दा अटॉर्नी जनरल द्वारा इस आधार पर उठाया गया था कि याचिकाकर्ता भारतीय केंद्रीय बैंक का निदेशक था और चालू खाते होने के अलावा उक्त बैंक और अन्य बैंकों में भी शेयर रखता था। रखरखाव के मुद्दे को खारिज करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि राहत देने के लिए अदालतों के अधिकार क्षेत्र से इनकार नहीं किया जा सकता है जब राज्य की कार्रवाई से व्यक्तिगत शेयरधारक के अधिकार बाधित हो जाते हैं और यदि उक्त कार्रवाई की जाती है।

7 1970 (1) एस. सी. सी. 248 आई. एम. टी. औद्योगिक संघ और ए. एन. डी. आर. बनाम राज्य

167

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

यह विचार रखते हुए कि बैंकों का अपना बैंकिंग व्यवसाय चलाने का अधिकार छीन लिया जा रहा है। आर. सी. कूपर का प्रासंगिक भाग मामला (ऊपर) इस प्रकार हैः -

“14. मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ रिट के लिए प्रार्थना करने वाली याचिका द्वारा, एक ऐसे मामले को छोड़कर जहां याचिका बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के लिए है और संभवतः कला के तहत गारंटी के उल्लंघन के लिए है। 17, 23 और 24, याचिकाकर्ता अपने अधिकारों के संबंध में राहत मांग सकता है न कि दूसरों के। यह सच है कि किसी कंपनी का शेयरधारक उसकी परिसंपत्तियों का मालिक नहीं है; उसे केवल संगठन के अनुच्छेदों में निहित अनुबंध के अधीन कंपनी के लाभ में भाग लेने का अधिकार है। लेकिन इस वजह से याचिकाएं विफल नहीं होंगी। एक कार्यकारी या विधायी उपाय अकेले कंपनी के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है, न कि उसके शेयरधारकों के; यह शेयरधारकों के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है न कि कंपनी केः यह शेयरधारकों के साथ-साथ कंपनी के अधिकारों को भी प्रभावित कर सकता है। राहत देने के लिए न्यायालय की अधिकारिता से इनकार नहीं किया जा सकता है, जब राज्य की कार्रवाई से व्यक्तिगत शेयरधारक के अधिकार बाधित हो जाते हैं, अगर वह कार्रवाई कंपनी के अधिकारों को भी बाधित करती है। यह निर्धारित करने में परीक्षण कि क्या शेयरधारक का अधिकार बाधित है, औपचारिक नहीं हैः यह अनिवार्य रूप से गुणात्मक हैः यदि राज्य की कार्रवाई शेयरधारकों के साथ-साथ कंपनी के अधिकार को बाधित करती है, तो न्यायालय, केवल कार्रवाई के तकनीकी संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, राहत देने के लिए खुद को अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं करेगा। 15. याचिकाकर्ता का दावा है कि अधिनियम और अध्यादेश द्वारा कला के तहत उसे अधिकारों की गारंटी दी गई है। 14, 19 और संविधान की 31 धारा बाधित हैं। उनका कहना है कि अधिनियम और अध्यादेश विधायी क्षमता के बिना हैं क्योंकि वे व्यापार की स्वतंत्रता की गारंटी में हस्तक्षेप करते हैं और जनहित में नहीं बनाए गए हैं। कि संसद के पास अधिनियम को लागू करने के लिए कोई विधायी क्षमता नहीं थी और राष्ट्रपति के पास आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा को लागू करने की कोई शक्ति नहीं थी।

2024(1)

168

16. XXX XXX XXX 17. भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड और अन्य बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापत्तनम और अन्य (2) मामले में इस न्यायालय के फैसले का इस प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं है। उस मामले में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका में राज्य व्यापार निगम ने संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (च) और (छ) के तहत संपत्ति रखने और व्यवसाय करने के अपने अधिकार के उल्लंघन को चुनौती दी और इस न्यायालय ने राय दी कि निगम नागरिक नहीं होने के नाते अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को लागू करने में अक्षम था। न ही टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड बनाम में निर्णय है। बिहार राज्य और अन्य. इन याचिकाओं में उत्पन्न होने वाले प्रश्न पर कोई संबंध। बिहार राज्य द्वारा बिक्री-कर लगाने को चुनौती देने वाली एक कंपनी द्वारा दायर संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका में दो शेयरधारकों को भी याचिकाकर्ता के रूप में शामिल किया गया था। शेयरधारकों की ओर से यह आग्रह किया गया था कि वास्तव में कंपनी और शेयरधारकों के हित समान हैं और शेयरधारक याचिका को बनाए रखने के हकदार हैं। अदालत ने उस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कंपनी प्रत्यक्ष रूप से जो हासिल नहीं कर सकी, वह अप्रत्यक्ष रूप से "पर्दा उठाने के सिद्धांत" पर भरोसा नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता इस मामले में अपने स्वयं के अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती देना चाहता है न कि आई. एम. टी. औद्योगिक संघ के बैंकों और अन्य बनाम राज्य के।

169

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

18. XXX XXX XXX 19. यह विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या संविधान का अनुच्छेद 31 ए (1) (डी) याचिकाकर्ता के निदेशक के रूप में अपने अधिकारों को लागू करने के दावे को रोकता है। अधिनियम प्रथम दृष्टया (यद्यपि अध्यादेश कथित रूप से) निदेशक के रूप में याचिकाकर्ता के अधिकार को समाप्त या संशोधित करने का प्रयास नहीं करता हैः यह बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए नामित बैंकों के अधिकार को स्पष्ट रूप से छीनने का प्रयास करता है, जबकि बैंकिंग के अलावा अन्य व्यवसाय करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखता है। यह मानते हुए कि वह एक निदेशक के रूप में अपने गारंटीकृत अधिकारों को लागू करने के अपने अधिकार को स्थापित करने का हकदार नहीं है, याचिका तब भी विफल नहीं होगी। याचिकाओं की स्थिरता के खिलाफ महान्यायवादी द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति विफल होनी चाहिए। I. 1969 के अध्यादेश 8 की वैधता। ”

(25) रिलायंस को 5-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर रखा जा सकता है

8 1973 (2) एससीआर 757 9 1959 एससीआर 12

10 1962 3 एस. सी. आर. 842 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

170

खारिज कर दिया। प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः - “22. बैंक राष्ट्रीयकरण मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (च) और 19 (1) (छ) के तहत अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए क़ानून को अमान्य ठहराया। बैंक राष्ट्रीयकरण मामले (उपरोक्त) में याचिकाकर्ता उस कंपनी का एक शेयरधारक और निदेशक था जिसे क़ानून के तहत अधिग्रहित किया गया था। बैंक राष्ट्रीयकरण मामले (उपरोक्त) के परिणामस्वरूप न्यायालय यह पता लगाता है कि क्या विधायी उपाय सीधे उस कंपनी को छूता है जिसमें याचिकाकर्ता एक शेयरधारक है। एक शेयरधारक अनुच्छेद 19 के संरक्षण का हकदार है। वह व्यक्तिगत अधिकार इस तथ्य के कारण नहीं खोता है कि वह कंपनी का शेयरधारक है। बैंक राष्ट्रीयकरण मामले (उपरोक्त) ने इस दृष्टिकोण को स्थापित किया है कि नागरिकों के रूप में शेयरधारकों के मौलिक अधिकार तब नहीं खोते हैं जब वे किसी कंपनी से जुड़ते हैं। जब शेयरधारकों के रूप में उनके मौलिक अधिकार राज्य की कार्रवाई से बाधित होते हैं तो शेयरधारकों के रूप में उनके अधिकार सुरक्षित होते हैं। इसका कारण यह है कि शेयरधारकों के अधिकार समान रूप से और आवश्यक रूप से प्रभावित होते हैं। कंपनी के अधिकार प्रभावित होते हैं। अनुच्छेद 19 (1) (ए) के संबंध में शेयरधारकों के अधिकारों को निगम के माध्यम से शेयरधारकों के स्वामित्व और नियंत्रण वाले समाचार पत्रों द्वारा प्रस्तुत और प्रकट किया जाता है। वर्तमान मामले में, संपादकों, निदेशकों और शेयरधारकों के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकारों का प्रयोग उनके समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाता है, जिनके माध्यम से वे बोलते हैं। प्रेस समाचार पत्रों के माध्यम से जनता तक पहुँचता है। शेयरधारक अपने संपादकों के माध्यम से बोलते हैं-यह तथ्य कि कंपनियां याचिकाकर्ता हैं, इस न्यायालय को उन शेयरधारकों, संपादकों, प्रिंटरों को राहत देने से नहीं रोकता है जिन्होंने कानून के प्रभाव और उनके अधिकारों पर कार्रवाई के कारण अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग की है। बैंक राष्ट्रीयकरण मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले के बाद शेयरधारक याचिकाकर्ताओं का अधिकार क्षेत्र चुनौती से परे है। कंपनी की उपस्थिति उसी फैसले पर है न कि राहत देने पर रोक।

23. सकल पेपर्स मामले (ऊपर) और एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स मामले (ऊपर) के फैसले भी कार्यवाही को बनाए रखने के लिए याचिकाकर्ताओं की क्षमता का समर्थन करते हैं। ”

आई. एम. टी. औद्योगिक संघ और एक अन्य बनाम राज्य

171

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक बार कानून के समक्ष समानता से इनकार करने की शिकायत होने पर, प्रारंभिक आपत्ति को खारिज करना पड़ा और चक्र को गति देना न्यायालय का काम था। यह माना गया था कि राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति के बीच शाही युद्ध पर ध्यान दिया जाना चाहिए और लैसेज़ फेयर का सिद्धांत लागू हो गया था और राज्य नियंत्रण को कमोबेश स्पष्ट होना था क्योंकि " जो सरकार सबसे कम शासन करती है, वह सबसे अच्छा शासन करती है। दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स के मामले (उपरोक्त) में प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैंः -

“13. इन याचिकाओं में मौलिक अधिकारों के कथित उल्लंघन का छल किसी को धोखा न दे; किसी को भी संदेह न हो कि याचिकाएं कुछ मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण को सही साबित करने के लिए दायर की गई हैं, जिन पर नाराजगी है। जड़ में राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति के बीच एक दूसरे पर प्रभुत्व हासिल करने के लिए भयंकर और अंतहीन युद्ध शाही है। कानूनी लोगों के पर्दे को छेदना मूल सवाल राज्य द्वारा लगाए गए सामाजिक नियंत्रण का स्तर है और कॉर्पोरेट क्षेत्र के आंतरिक प्रशासन में कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा हर मोड़ पर इसका विरोध किया जाता है। इसलिए, कंपनी कानून के विकास के बारे में पक्षियों का दृष्टिकोण जो कंपनियों के प्रबंधन में राज्य के हस्तक्षेप का प्रतिनिधित्व करता है, फायदेमंद होगा।

14. हमारे देश में कंपनी कानून के इतिहास को प्रस्तुत करने का कोई भी वैज्ञानिक प्रयास अनिवार्य रूप से यू. के. में कंपनी कानून के इतिहास में दूरबीन है क्योंकि भारत में कंपनी कानून के निर्माता कम या ज्यादा यू. के. में कानून के विकास की छाया में अनुसरण करते हैं। कॉर्पोरेट क्षेत्र जबरदस्त आर्थिक शक्ति का उपयोग करता है और यह 11 1983 (4) एस. सी. सी. 166 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

172

संगठित क्षेत्र ने अपने नियंत्रण में सभी तरीकों से, राजनीतिक संस्थानों और विशेष रूप से राज्य द्वारा सामाजिक नियंत्रण को चुनौती दी है। यह कानून अपनी आर्थिक शक्ति के कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा दुरुपयोग और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्योग, व्यापार और वाणिज्य की दुनिया में हावी प्रभाव के नक्शेकदम पर विकसित हुआ। यदि अनियंत्रित है, तो परिणाम विनाशकारी है और कुख्यात दक्षिण-सागर बुलबुला एक आंख खोलने वाला होना चाहिए। 18वीं शताब्दी के पहले और दूसरे दशकों में कंपनी के फ्लोटेशन में लगभग उन्मादी उछाल आया था। जब सट्टा उद्यमों की बाढ़ अपने चरम पर थी, यू. के. में संसद ने जुआ उन्माद को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का फैसला किया जब इसने कई उपक्रमों की ओर ध्यान आकर्षित किया जो कानूनी अधिकार के बिना कॉर्पोरेट निकायों के रूप में कार्य करने का इरादा रखते थे, ऐसी प्रथाएं जो स्पष्ट रूप से राज्य के सार्वजनिक व्यापार और वाणिज्य के पूर्वाग्रह की ओर प्रवृत्त होती हैं। (1) जो सबसे कम को नियंत्रित करता है, सबसे अच्छे को नियंत्रित करता है, वह लैसेज़ फेयर सिद्धांत दृढ़ता से स्थापित था। तब से नियमित अंतराल पर, लगातार कंपनी अधिनियमों में राज्य का नियंत्रण कमोबेश स्पष्ट हो गया। ”

(28) परिणामस्वरूप, हम याचिकाकर्ताओं के पक्ष में और राज्य के खिलाफ प्रश्न संख्या 1 का निर्णय लेते हैं और मानते हैं कि याचिकाएं हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए बनाए रखने योग्य।

प्रश्न संख्या 2 का उत्तर जो है (क्या यह इसके भीतर था) आई. एम. टी. औद्योगिक संगठन में विचाराधीन मुद्दे पर कानून बनाने के लिए राज्य का अधिकार क्षेत्र और अन्य बनाम राज्य

173

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 35 के तहत प्रदान किए गए विशिष्ट प्रतिबंध का दृष्टिकोण और क्या यह कानून संघ सूची की प्रविष्टि No.81 के तहत शामिल होगा? ).

(29) राज्य का बचाव उतना ही दिलचस्प है जितना कि वरिष्ठ वकील द्वारा उठाई गई दलीलें जो दलील दी गई है, उसके विपरीत हैं। श्री बाली ने इस तथ्य पर जोर दिया है कि याचिकाकर्ताओं के वकील प्रवास के मुद्दे को राज्य के कानून के दायरे से बाहर लाने के लिए संदर्भ से बाहर पढ़ रहे हैं और इसे संघ सूची की प्रविष्टि No.81 के तहत शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। यह उनका तर्क रहा है कि इस अधिनियम का उद्देश्य केवल हरियाणा के निवासियों के जीवन और आजीविका की गुणवत्ता को बढ़ाना और उन्हें उनके जीवन और आजीविका की खराब गुणवत्ता के दलदल से बाहर निकालना था। तदनुसार यह तर्क दिया गया कि केवल इसलिए कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में "प्रवासी" शब्द का उपयोग किया गया था, इस प्रकार क़ानून को राज्य के विधान के दायरे से बाहर नहीं लाएगा। इसका उद्देश्य स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना और स्थानीय कार्यबल को प्रशिक्षित करना था और यह आम जनता के हित में था। (30) तदनुसार, यह तर्क दिया गया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 16, जो सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर प्रदान करता है, नागरिक के अधिकार के बारे में बात करता है न कि किसी संगठन के। उपखंड (2) ने जन्म स्थान के कारण अयोग्यता या भेदभाव का प्रावधान किया जो राज्य के तहत किसी भी रोजगार के संबंध में केवल एक नागरिक था। तदनुसार यह प्रस्तुत किया गया कि किसी भी सार्वजनिक रोजगार के संबंध में राज्य की ओर से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इसलिए, इस तरह की चुनौती बिना किसी आधार के थी। यह आगे तर्क दिया गया कि यह एक उचित प्रतिबंध था जो अनुच्छेद 19 (5) और 19 (6) के प्रावधानों के तहत अनुमत था जो आम जनता के हित में था। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि संविधान के विभिन्न भागों से कोई जोड़ या घटाव नहीं हो सकता है और इसे एक साथ पढ़कर भ्रमित नहीं किया जा सकता है। संविधान के सही अक्षर और भावना को देखना था। अनुच्छेद 15 (4) पर भरोसा करते हुए, यह बताया गया कि नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करना राज्य के लिए अनुमत है, हालांकि राज्य के लिए जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषिद्ध था। इसी तरह, खंड 15 (6) (ए) का उल्लेख करते हुए, यह बताया गया कि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए एक विशेष प्रावधान है जो राज्य को शक्ति देता है।

(31) तदनुसार यह तर्क दिया गया कि पूरा उद्देश्य आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा के लिए था।

2024(1)

174

मेसर्स होक्स्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ इंडिया पर निर्भरता बिहार और अन्य 15, यह तर्क दिया गया था कि केवल अगर सुलह संभव नहीं है, तो अनुच्छेद 246 (1) में गैर-अस्थांत खंड काम करेगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 35 इस प्रकार हैः -

(क) संसद के पास कानून बनाने की शक्ति होगी और किसी राज्य के विधानमंडल के पास - (i) उन मामलों में से किसी के संबंध में जिनके लिए अनुच्छेद 16 के खंड (3), अनुच्छेद 32 के खंड (3), अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के तहत संसद द्वारा बनाई गई कानून द्वारा प्रावधान किया जा सकता है; और

14 1994 (3) एस. सी. सी. 569

15 1983 4 एस. सी. सी. 45 आई. एम. टी. औद्योगिक संघ और ए. एन. डी. आर. बनाम राज्य

175

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

((ख) उन कार्यों के लिए दंड विहित करने के लिए जिन्हें इस भाग के तहत अपराध घोषित किया गया है, और संसद, इस संविधान के प्रारंभ के बाद जितनी जल्दी हो सके, उपखंड (ii) में निर्दिष्ट कार्यों के लिए दंड निर्धारित करने के लिए कानून बनाएगी। (ख) खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट मामलों में से किसी के संबंध में या उस खंड के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए दंड का प्रावधान करने के संबंध में भारत के राज्यक्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ से तुरंत पहले लागू कोई कानून, उसकी शर्तों और अनुच्छेद 372 के तहत उसमें किए जाने वाले किसी भी अनुकूलन और संशोधनों के अधीन रहते हुए, संसद द्वारा परिवर्तित या निरस्त या संशोधित किए जाने तक लागू रहेगा।

(32) उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि अनुच्छेद 16 (3) के तहत आने वाले मामलों के संबंध में कोई कानून नहीं बनाने के लिए राज्य के विधानमंडल के लिए एक विशिष्ट प्रतिबंध है। वही आगे प्रावधान करता है कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता होनी चाहिए। उपखंड (3) के तहत दी गई शक्ति केवल सरकार के तहत किसी पद पर या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के तहत किसी पद पर नियुक्ति के वर्ग या वर्गों के संबंध में कोई कानून बनाने के लिए संसद को दी गई है, बशर्ते कि ऐसी नियुक्ति या नियुक्ति से पहले उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास की आवश्यकता हो। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 इस प्रकार हैः -

(2) कोई भी नागरिक, केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या उनमें से किसी के आधार पर, राज्य के तहत किसी भी रोजगार या पद के लिए अयोग्य या भेदभाव नहीं किया जाएगा। (3) इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार या उसके भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के तहत किसी पद पर नियुक्ति या नियुक्ति के किसी वर्ग या वर्गों के संबंध में ऐसी नियुक्ति या नियुक्ति से पहले उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास की कोई आवश्यकता निर्धारित करने वाली कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

176

(5) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगी जो यह प्रावधान करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के मामलों के संबंध में किसी पद का अवलंबी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशेष धर्म का पालन करने वाला या किसी विशेष संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति होगा। (6) इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को मौजूदा आरक्षण के अलावा और अधिकतम दस प्रतिशत के अधीन रहते हुए, खंड (4) में उल्लिखित वर्गों के अलावा नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। प्रत्येक श्रेणी में पद। ”

(33) यद्यपि श्री बाली इस हद तक सही हो सकते हैं कि यह विशेष रूप से सार्वजनिक रोजगार के संबंध में है, लेकिन तथ्य यह है कि इस देश के नागरिकों के साथ उनके जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर रोजगार से संबंधित भेदभाव के संबंध में संविधान के तहत एक प्रतिबंध है और उन्हें अयोग्य आई. एम. टी. औद्योगिक संघ और अन्य बनाम राज्य

177

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

या राज्य के लिए रोजगार के संबंध में भेदभाव किया गया। हम प्रश्न संख्या 3 के तहत उक्त मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे।

(34) श्री गुप्ता ने निर्णय पर सही भरोसा किया है

आंध्र प्रदेश और अन्य 16 ने उनके तर्क के समर्थन में, जिसमें संविधान पीठ के समक्ष सवाल यह था कि सभी गैर-अधिवासी व्यक्तियों को तेलंगाना क्षेत्र के अधिवास की वरीयता में सेवा से मुक्त किया जाना था। उन्हें अतिरिक्त पदों का सृजन करके आंध्र प्रदेश क्षेत्र में बिना सेवा विराम के रोजगार दिया जाना था। इस प्रकार, मुद्दा संसद की कानून बनाने की शक्ति और जन्म स्थान और निवास के आधार पर भेदभाव का बन गया। नतीजतन, अनुच्छेद 35 (ए) पर भरोसा करते समय, इस सवाल पर विचार किया गया कि क्या संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास की आवश्यकता को निर्धारित करने वाला कानून बना सकती है और क्या इस शक्ति को प्रत्यायोजित किया जाएगा। नतीजतन, यह तर्क स्वीकार कर लिया गया कि संविधान में पूरे राज्य को आवासीय योग्यता के लिए स्थान के रूप में बताया गया है और श्री सीतलवाड़ द्वारा प्रस्तावित संकीर्ण निर्माण को खारिज कर दिया गया था, जबकि सार्वजनिक रोजगार (निवास के रूप में आवश्यकता) अधिनियम, 1957 की धारा 3 के तहत पारित आदेशों को रद्द कर दिया गया था। द. ए. वी. एस. नरसिम्हा राव के मामले (उपरोक्त) में प्रासंगिक पैरा इस प्रकार हैः -

(1) राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। "(2) कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग वंश, जन्म स्थान, निवास या उनमें से किसी के आधार पर राज्य के तहत किसी भी रोजगार या पद के लिए अयोग्य नहीं होगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।

(3) इस अनुच्छेद की कोई भी बात संसद को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार या उसके भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के तहत किसी पद पर किसी वर्ग या वर्ग के रोजगार या नियुक्ति के संबंध में कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी, 16 1969 (1) एस. सी. सी. 839 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

178

5. सवाल इस अनुच्छेद के निर्माण का है, विशेष रूप से पहले तीन खंडों में से, संसद की कानून बनाने की शक्ति के दायरे का पता लगाने के लिए। पहले खंड में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत में राज्य के तहत किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। यहाँ 'राज्य' शब्द को अनुच्छेद 12 में उस शब्द की परिभाषा द्वारा दिए गए विस्तारित अर्थ में समझा जाना चाहिए। दूसरा खंड तब केवल धर्म, नस्ल, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव के खिलाफ निषेध को निर्दिष्ट करता है। यहाँ का उद्देश्य प्रत्येक कार्यालय या रोजगार को प्रत्येक नागरिक के लिए खुला और उपलब्ध कराना है, और अन्य बातों के साथ-साथ भारत के किसी एक हिस्से में कार्यालय या रोजगार को भारत के अन्य सभी हिस्सों में नागरिकों के लिए खुला रखना है। तीसरा खंड तब एक अपवाद बनाता है। इस खंड को संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा संशोधित किया गया था। पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी राज्य या उसके क्षेत्र के भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के तहत खंड के मूल शब्दों के लिए उस राज्य के भीतर निवास की किसी भी आवश्यकता के लिए, वर्तमान शब्दों को 'सरकार के तहत' से 'केंद्र शासित प्रदेश' में प्रतिस्थापित किया गया है। उस संशोधन पर कुछ भी नहीं होता है जो खंड में अपवाद को केंद्र शासित प्रदेश पर लागू करने और भाषा में अस्पष्टता को दूर करने का प्रयास करता है। 6. इस प्रकार खंड संसद को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रोजगार की शर्त के रूप में नियुक्ति से पहले किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास के रूप में किसी भी आवश्यकता को निर्धारित करने वाले विशेष मामले में कानून बनाने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 35 (ए) के तहत यह शक्ति संसद को प्रदान की गई है, लेकिन संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, राज्यों के विधानमंडलों को इससे वंचित कर दिया गया है, और (बी) मामले के संबंध में संविधान के प्रारंभ से तुरंत पहले लागू कोई भी कानून उसकी शर्तों के अधीन होगा और अनुच्छेद 372 के तहत किए जाने वाले ऐसे अनुकूलन के अधीन रहते हुए संसद द्वारा परिवर्तित या निरस्त या संशोधित किए जाने तक लागू रहना है।

आई. एम. टी. औद्योगिक संघ और एक अन्य बनाम राज्य

179

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

XXX XXX XXX

9. दूसरी ओर, श्री सीतलवाड़ अपने तर्क को दो बातों पर आधारित करते हैं। उनका तर्क है कि संसद को कोई भी कानून बनाने की शक्ति दी गई है और इसलिए, संसद सर्वोच्च है और इस विषय पर कोई भी कानून बना सकती है जैसा कि लेख में कहा गया है। उन्होंने बहुत चतुराई से 'एक आवश्यकता' शब्दों पर जोर दिया और तर्क दिया कि आवश्यकता राज्य या राज्य के किसी विशेष हिस्से में निवास के बारे में हो सकती है। 10. संसद की सर्वोच्चता का दावा गलत है। अन्य मामलों की तरह इस मामले में भी संसद सर्वोच्च है जहां तक संविधान इसे बनाता है। जहाँ संविधान सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करता है, वहाँ संसद को अपने निर्धारित कार्यों के भीतर कार्य करना चाहिए और उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। संविधान जो कहता है वह संविधान की भाषा के निर्माण का मामला है। सुझाए गए दोनों का उचित निर्माण कौन सा है? पहले खंड द्वारा रोजगार या किसी पद पर नियुक्ति में अवसर की समानता की गारंटी दी गई है। दूसरे खंड के अनुसार, अन्य बातों के अलावा, निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। हालाँकि, यह महसूस करते हुए कि कभी-कभी स्थानीय भावनाओं का सम्मान करना पड़ सकता है या कभी-कभी अधिक उन्नत राज्यों से कम विकसित राज्यों में प्रवेश को रोकना पड़ सकता है, और इसलिए, एक आवासीय योग्यता निर्धारित करनी पड़ सकती है, खंड (3) में अपवाद बनाया गया था। फिर भी, उस खंड में राज्य के भीतर निवास की बात की गई थी। श्री सीतलवाड़ का यह दावा कि संसद किसी राज्य के किसी विशेष हिस्से में निवास के संबंध में प्रावधान कर सकती है, सामान्य निषेध को अपना सारा अर्थ खो देगा। 'कोई भी आवश्यकता' शब्दों को किसी ऐसी चीज की पुष्टि करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है जिसे अधिक विशेष रूप से कहा जा सकता था। ये शब्द राज्य के भीतर इसके स्थान के बजाय निवास के प्रकार या इसकी अवधि पर निर्भर करते हैं। हम श्री गुप्ते के इस तर्क को स्वीकार करते हैं कि संविधान, जैसा कि यह है, एक पूरे राज्य को आवासीय योग्यता के लिए स्थान के रूप में बताता है और यह सोचना असंभव है कि संविधान सभा जिलों, तालुकों, शहरों, कस्बों या गांवों में निवास के बारे में सोच रही थी। यह तथ्य कि यह खंड एक अपवाद है और एक संशोधन के रूप में आया है, यह निर्धारित करना चाहिए कि आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा के अपवाद पर एक संकीर्ण संरचना

2024(1)

180

इसे रखा जाना चाहिए क्योंकि वास्तव में संविधान सभा में बहस भी संकेत देती प्रतीत होती है। हम तदनुसार श्री सीतलवाड़ के उस तर्क को अस्वीकार करते हैं जिसमें उन्होंने 'कोई भी कानून' और 'कोई भी आवश्यकता' शब्दों पर एक बहुत व्यापक और उदार निर्माण करने की मांग की थी। ये शब्द स्पष्ट रूप से 'राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास' शब्दों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिन शब्दों का अर्थ वे क्या कहते हैं, न तो अधिक और न ही कम। इसलिए, यह इस प्रकार है कि सार्वजनिक रोजगार (निवास की आवश्यकता) अधिनियम, 1957 की धारा 3, जहां तक यह तेलंगाना से संबंधित है (और हम अन्य भागों के बारे में कुछ नहीं कहते हैं) और इसके तहत नियमों के नियम 3 संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। 11. इस बिंदु पर हमारे निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए यह राय व्यक्त करना आवश्यक नहीं है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को आगे लागू करने के लिए नियमों द्वारा प्रदान करने के लिए केंद्र और/या राज्य सरकारों को प्रत्यायोजन वैध है या नहीं। ”

कांच के मामले को ऐतिहासिक जिज्ञासा के रूप में देखा जाएगा "यदि लेख 14, 19 और 21 को 42वें संशोधन के मुद्दे पर विस्तार करते हुए स्वर्ण त्रिकोण से हटा दिया गया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह संसद की संशोधन शक्ति से परे है और संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर सीमाएं हैं और यह इसकी मूल या आवश्यक विशेषता को नष्ट नहीं कर सकता है। इस प्रकार, इन तीन अनुच्छेदों को संविधान का मुख्य प्रतीक कहा गया था और भाग III के तहत गारंटी दी गई थी और भारत के संविधान के भाग IV के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हुए इन्हें नष्ट नहीं किया जा सका था। 1969 आई. एम. टी. औद्योगिक संघ और ए. एन. ए. एन. वी. एस. स्टेट ऑफ इंडिया से शुरू होने वाली पिछली आधी सदी की न्यायिक मिसाल।

181

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

18 2017 (10) एससीसी 1

19 1900 (179) यू. एस. 270 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

182

उक्त न्यायाधीश की दूरदर्शिता ने "बस सांस ली" जिसमें 20 साल बाद संवैधानिक कानून के परिवर्तनों की प्रत्याशा में और अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19 (1) (डी) के तहत आवाजाही की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करना चर्चा का विषय था। उस समय उनके शब्द "जंगल में एक शोर था" और यह कि अनुच्छेद 21 में परिलक्षित संवैधानिक मूल्य राज्य के हित या सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए राज्य द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन एक अधिकार थे। हालाँकि, यह माना गया है कि जिस अभ्यास से संबंधित अधिकार का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए और राज्य की कार्रवाई को रोका जा सकता है यदि यह मनमाना और अनुचित है और इसे व्यक्तिगत, सामाजिक और राज्य के हित के बीच संतुलन बनाते हुए पारित करना पड़ता है और अभ्यास न्यायिक दिमाग द्वारा किया जाना चाहिए। (38) 20 ए. आई. आर. 1950 एस. सी. 27 आई. एम. टी. के अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 5 का उल्लेख करते हुए आई. एम. टी. औद्योगिक संघ और अन्य बनाम राज्य

183

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

भारत के संविधान और संविधान के मसौदे पर बहस और चर्चाओं में यह तर्क दिया गया है कि भारत एक अभिन्न अंग है और यह एक अविनाशी इकाई है, लेकिन प्रशासन की सुविधा के लिए इसे केवल विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया था और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह एक उद्देश्य के देश के रूप में और बिना किसी दोहरी नागरिकता के एकल साम्राज्य के तहत रहने वाले लोगों के रूप में सन्निहित किया गया था। एकल साम्राज्य एक ही स्रोत से उत्पन्न हुआ था जो राष्ट्र को एकजुट और संविधान को जीवित रख रहा था। यदि क्षेत्र विभाजित किया जाता, तो लोग विभाजित हो जाते, राज्य अपने स्वयं के संविधान का मसौदा तैयार करना शुरू कर देते। इस प्रकार, संस्थापक पिताओं द्वारा परिकल्पित वाणिज्यिक संभोग नष्ट हो जाएगा। न्यायमूर्ति पी. एन. कृष्ण अय्यर की टिप्पणियों से मेनका गांधी बनाम भारत संघ 21 का उल्लेख करते हुए कि अधिनायकवादी आदेश और पूरे समुदायों और संस्कृतियों द्वारा रचनात्मक गतिशीलता को रोकने के लिए ठहराव होगा और अंततः हम स्वामी विवेकानंद द्वारा पकड़े गए "एक कुएं में मेंढक" (कुपा मंडुका) बन जाएंगे। नागरिकता की आवश्यक विशेषताएँ आवाजाही की स्वतंत्रता थी और यात्रा का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शुरू किए गए मूल्यों की योजना में बुनियादी थी। तदनुसार यह तर्क दिया गया था कि भारत के संविधान के भाग-III में कोई भी अनुच्छेद एक द्वीप नहीं था, लेकिन वे एक महाद्वीप का हिस्सा हैं।

(39) आई. आर. कोएल्हो के मामले (ऊपर) पर सही रूप से वापस आते हुए, यह हो सकता है

उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 किसी भी काल्पनिक अधिकार को प्रदान नहीं कर रहे हैं और यदि अनुच्छेद 19 (1) (डी) उपलब्ध नहीं होता तो क्षेत्रीय रूढ़िवाद का एक व्यावहारिक दिन होता। यह देखा जा सकता है कि 1980 के दशक में उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय राजनीति के कुछ हिस्सों में परेशान करने वाले रुझानों को पहले ही देख लिया था। तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय को संविधान की व्याख्या इस तरह से करनी चाहिए जो नागरिकों को उसके द्वारा गारंटीकृत अधिकारों का पूरा लाभ उठाने में सक्षम बनाए और अनुच्छेद 14 और 19 को प्रवर्तन से बाहर नहीं रखा जा सकता है। (40) याचिकाकर्ताओं के वकीलों का यह तर्क देना सही है कि जो देखा जाना है वह कानून का सार और सार है। कानून का अंतर्निहित उद्देश्य, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा संक्षिप्त रूप से रखा गया है, भारत के नागरिकों के लिए एक कृत्रिम अंतर और भेदभाव पैदा करना है। इस कानून का उद्देश्य स्वयं इस तथ्य पर आधारित है कि बड़ी संख्या में प्रवासी हैं जो स्थानीय उम्मीदवारों की नौकरी कर रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से तुलनात्मक रूप से कम वेतन वाले हैं और राशि को Rs.50,000/- प्रति माह से घटाकर Rs.30,000/- प्रति माह कर दिया गया है। यह 21 1978 (1) एस. सी. सी. 248 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा में है।

2024(1)

184

शाह गोवर्धन एल. काबरा टीचर्स कॉलेज 22 जिसमें यह आयोजित किया गया था। कि संघ की शक्ति का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता था। यह विवादित नहीं है कि प्रवास का मुद्दा संघ सूची की प्रविष्टि No.81 के तहत शामिल है। इस प्रकार, क़ानून का अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि नियोक्ता की संख्या के 75 प्रतिशत के लिए देश के बाकी हिस्सों से अपने कर्मचारियों को उन लोगों में से रखने की अनुमति नहीं है जो प्रति माह <ID1,000/- से कम कमा रहे हैं। अंतिम प्रभाव यह है कि नियोक्ता के पास राज्य की कार्रवाई के कारण अपना कार्यबल चुनने का सीमित विवेक रह जाता है। स्थानीय उम्मीदवार को हरियाणा राज्य में अधिवासित व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया था। (41) तदनुसार हमारे ध्यान में लाया गया कि अधिनियम की धारा 2 (ई) के तहत नियोक्ता की परिभाषा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी के बारे में थी; हरियाणा पंजीकरण और सोसायटी अधिनियम, 2012 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी; सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत सीमित देयता भागीदारी फर्म; भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत परिभाषित ट्रस्ट और भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत परिभाषित साझेदारी फर्म, जो संस्थाएं अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगी। दूसरी ओर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या उनमें से किसी के स्वामित्व वाले संगठन को बाहर रखा गया है। धारा 2 (जी) ने आगे प्रावधान किया कि एक स्थानीय उम्मीदवार एक ऐसा उम्मीदवार था जो हरियाणा राज्य में और हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार नियम, 2021 के तहत अधिवासित था, जो 10.01.2022 से अधिनियम के साथ लागू हुआ था। प्रासंगिक नियम 2 (बी) इस प्रकार हैः -

“2(ख) "अधिवासी व्यक्ति" से हरियाणा का एक वास्तविक निवासी अभिप्रेत है जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली शर्तों को पूरा करता है और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के तहत परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) जारी किया गया है;

(42) अधिवासी व्यक्ति वह था जो वास्तविक निवासी था।

22 2002 (8) एस. सी. सी. 228 आई. एम. टी. औद्योगिक संघ और ए. एन. डी. आर. बनाम राज्य

185

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई शर्तों को पूरा करने और हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम No.20) (संक्षेप में 'पहचान अधिनियम, 2021') के तहत जारी परिवार पहचान पत्र (PPP) होना। नतीजतन, पहचान अधिनियम, 2021 का संदर्भ दिया गया कि यह परिवारों की विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है और राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों की ओर से किसी भी योजना या सब्सिडी को लागू करने के उद्देश्यों के लिए काम करेगा। निवासी की परिभाषा को धारा 2 (टी) और धारा 3 के तहत संदर्भित किया गया था, जिसमें परिवार को पहचान संख्या प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया था। धारा 2 (टी) और धारा 3 के तहत निवासी की प्रासंगिक परिभाषा इस प्रकार हैः -

((च) "राज्य सरकार" से प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार अभिप्रेत है; ((घ) "सब्सिडी" से किसी व्यक्ति या परिवार को नकद या किसी प्रकार की सहायता, सहायता, अनुदान, अनुदान या विनियोग का कोई भी रूप अभिप्रेत है और इसमें हरियाणा राज्य की संचित निधि से पूरी तरह या आंशिक रूप से प्रदान की जाने वाली ऐसी अन्य सब्सिडी शामिल है। परिवार पहचान संख्या प्राप्त करने की पात्रता। 3. (1) हरियाणा राज्य का निवासी होने के नाते प्रत्येक परिवार, राज्य आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा द्वारा या उसकी ओर से प्रदान की गई या कार्यान्वित की गई किसी भी योजना, सेवा, सब्सिडी या लाभ के लिए पात्रता या प्रावधान निर्धारित करने के लिए, निर्दिष्ट पोर्टल पर ऐसी जानकारी प्रदान करके, जमा करके या अद्यतन करके परिवार पहचान संख्या प्राप्त करने का हकदार होगा, जिसे राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

2024(1)

186

सरकार या कोई सरकारी एजेंसी या स्थानीय प्राधिकरण। (2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य परिवार की जानकारी प्रदान, प्रस्तुत या अद्यतन कर सकता है। ”

(43) डॉ. प्रदीप जैन में निर्णय का उल्लेख करते हुए और

अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 23, यह बताया जा सकता है कि हालाँकि निर्णय प्रवेश से संबंधित था, लेकिन "अधिवास" शब्द के उपयोग पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की गई थी। यह तथ्य कि एक ही नागरिकता वाला एक राष्ट्र है और "एक राष्ट्र के रूप में भारत" की अवधारणा पर जोर देने और उसे बनाए रखने के संबंध में संविधान निर्माताओं का सपना देखा गया और यह कि यह "भूमि के पुत्रों" के दावे के हाथों खतरे में पड़ गया है। यह भी देखा गया था कि अकेले संसद को निवास के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध और राज्य सरकार के रोजगार वाले पदों के संबंध में भी अपवाद लागू करने का अधिकार दिया गया था। सार्वजनिक रोजगार (निवास के रूप में आवश्यकता) अधिनियम, 1957, जो आंध्र प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों की रक्षा करता था, इस तथ्य पर ध्यान दिया गया कि राज्य सरकारें स्थानीयता की नीतियों का पालन कर रही थीं जो व्यापक हो गई थीं। परिणामस्वरूप, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 का उल्लेख करते हुए "भारत में अधिवास" नामक केवल एक अधिवास था, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि यदि इसका उपयोग वैध उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो यह देश की एकता और अखंडता को तोड़ देगा। इस प्रकार, यह उचित रूप से इंगित किया गया है कि उक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य द्वारा दिनांक 03.10.1996 के आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे कि "अधिवास" शब्द का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और "निवासी" शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए, जो निर्देश शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के उद्देश्य के लिए भी थे। उक्त दिशानिर्देशों में हरियाणा में रहने की 15 साल की अवधि प्रदान की गई है, इसके अलावा एक स्थायी घर और व्यवसाय के कारण यदि माता-पिता उक्त निर्देशों के खंड 5 (1) के अनुसार राज्य से बाहर रह रहे थे। इसके बाद उक्त निर्देशों को 14.01.2021 और 19.03.2022 पर अवधि को घटाकर 5 साल करने के लिए बदल दिया गया था, जिसमें पहली बार रोजगार के उद्देश्यों के लिए, उक्त अवधारणा को भी उन्हीं निर्देशों में पेश किया गया था।

दिनांकित 19.03.2022 निर्देश इस प्रकार हैंः -

“No.62/03/2021-6GS-I

23 1984 (3) एस. सी. सी. 654 आई. एम. टी. औद्योगिक संघ और ए. एन. डी. आर. बनाम राज्य

187

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग (सामान्य सेवा-I शाखा)

तारीखः चंडीगढ़ 19 मार्च, 2022

मुझे ऊपर दिए गए विषय पर सरकारी निर्देश संख्या 62/17/95-6GS-I, दिनांक 03.10.1996 और संख्या 62/03/2021-6GS-I, दिनांक 14.01.2021 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने और यह कहने का निर्देश दिया गया है कि सरकार ने निर्देशों के पैरा 1 (v) को आगे संशोधित करने का निर्णय लिया है। - 1((ए) हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम, 2020 के तहत हरियाणा निवासियों के रोजगार के उद्देश्य से और हरियाणा रोजगार और उद्यमिता नीति, 2020 या अन्य क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक नीतियों के तहत औद्योगिक इकाइयों को रोजगार सृजन सब्सिडी देने के उद्देश्य से-ऐसे व्यक्तियों के बच्चे/आश्रित/बच्चे (यदि माता-पिता नहीं रह रहे हैं) जिनके पास कम से कम पांच (5) वर्ष की अवधि से हरियाणा में स्थायी घर है; या जिनके पास पांच (5) वर्ष से कम की अवधि से हरियाणा में स्थायी घर है, लेकिन अपने व्यवसाय के कारण वे हरियाणा से बाहर रह रहे हैं; या जिनके पास स्थायी निवास नहीं है। आई. एल. आर में पंजाब और हरियाणा

2024(1)

188

(बी) प्रवेश, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता और सामाजिक-आर्थिक मानदंड के तहत वेटेज के उद्देश्य से-ऐसे व्यक्तियों के बच्चे/आश्रित/बच्चे (यदि माता-पिता जीवित नहीं हैं) जिनके पास कम से कम पंद्रह (15) वर्ष की अवधि से हरियाणा में स्थायी घर है; या जिनके पास पंद्रह (15) वर्ष से कम की अवधि से हरियाणा में स्थायी घर है, लेकिन अपने व्यवसाय के कारण वे हरियाणा से बाहर रह रहे हैं; या जिनके पास हरियाणा में स्थायी निवास नहीं है, लेकिन वे पंद्रह (15) वर्ष से कम की अवधि से हरियाणा में रह रहे हैं। 2. ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और कृपया सभी संबंधित लोगों के ध्यान में लाए जा सकते हैं।

यह अभिनिर्धारित किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि संसद के बार को अनुच्छेद 35 (ए) के तहत निवास की आवश्यकता के संबंध में एक विशेष मामले में कानून बनाने के लिए मान्यता दी गई थी और राज्य की विधानसभाओं को इससे इनकार कर दिया गया था। तदनुसार यह बताया गया कि 1957 के अधिनियम की धारा 3 और आंध्र प्रदेश सार्वजनिक रोजगार (निवास के रूप में आवश्यकता) नियम, 1959 के नियम 3 में भी

24 2003 (11) एस. सी. सी. 146 आई. एम. टी. औद्योगिक संघ और ए. एन. डी. आर. बनाम राज्य

189

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (ऊपर) के अधिकार पर विचार करते हुए गोपनीयता। व्यक्तियों और मुद्दों के प्रति मानसिक दृष्टिकोण को संविधान के मूल पाठ और भावना से पढ़ना होगा और समाज की लोकप्रिय धारणाओं और संवैधानिक संस्कृति को ध्यान में नहीं रखना होगा, जिसे बार-बार बहुमत के अत्याचार और सभी के प्रति सम्मान और सम्मान के दृष्टिकोण के खिलाफ एक रोक के रूप में माना जाता है। संवैधानिक न्यायालय द्वारा अधिकार खोने से ही लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा।

(46) टाटा पावर कंपनी लिमिटेड बनाम रिलायंस एनर्जी

लिमिटेड 25, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय अधिनियम के सही और सही निर्माण के लिए उद्देश्यों और कारणों के बयानों और उद्देश्य को समझने के उद्देश्य और अधिनियम के उद्देश्य पर गौर कर सकता है और सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत का सहारा लेने की आवश्यकता है।

(47) तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम के. श्याम

“66. अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि नई सरकार के आई. डी. 3 पर शपथ लेने के बाद, आई. डी. 2 पर पुरानी प्रणाली के तहत पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं और उसके बाद, आई. डी. 1 पर मंत्रिमंडल की बैठक में समान शिक्षा प्रणाली को लागू नहीं करने का निर्णय लिया गया। अधिनियम 2010 में संशोधन की पूरी कवायद सबसे जल्दबाजी में की गई। हालाँकि, जल्दबाजी में कार्यवाही करना अपने आप में किसी क़ानून की वैधता के लिए चुनौती का आधार नहीं हो सकता है, हालाँकि जल्दबाजी में कार्यवाही करना मनमानेपन के बराबर है और ऐसी तथ्य-स्थिति में प्रशासनिक आदेश रद्द होने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। ऊपर उल्लिखित तथ्यों से पता चलता है कि 25 2009 (16) एस. सी. सी. 659 की मंत्रिमंडल की बैठक से पहले ही पुरानी प्रणाली के तहत पढ़ाए जाने वाले पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के लिए 21.5.2011 पर निविदाएं आमंत्रित की गई थीं।

26 2011 (8) एस. सी. सी. 737 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

190

इस प्रकार, राज्य सरकार को अधिनियम 2010 की धारा 3 के प्रावधानों में संशोधन करने में किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है, विशेष रूप से ऐसी अनिश्चित शर्तों में। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय को दिया गया यह वचन कि अधिनियम 2010 को शैक्षणिक वर्ष में लागू किया जाएगा, अधिनियम 2011 को वैध ठहराने का एक अच्छा कारण नहीं हो सकता है। 68. अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत की गई दलीलें कि किसी अधिनियम के प्रारंभ की तारीख तय करना विधायिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र के भीतर है, और अदालत को ऐसे मामले में हस्तक्षेप करने की कोई क्षमता नहीं है, पूरी तरह से गलत धारणा है क्योंकि विधायिका ने अपने विवेक से अधिनियम के प्रारंभ की तारीखें निर्धारित की थीं, हालांकि चरणबद्ध तरीके से। अधिनियम तदनुसार लागू होने लगा। अदालतों ने विशिष्ट परिस्थितियों में मामले में हस्तक्षेप किया और इस संबंध में कुछ आदेश भी पारित किए। विधायिका उन फैसलों के प्रभाव को बिल्कुल भी नहीं मिटा सकी। तर्कों को पुष्ट करने के लिए उद्धृत निर्णय, विशेष रूप से ए. के. रॉय बनाम भारत संघ और आई. एम. टी. औद्योगिक संघ और ए. एन. ओ. आर. बनाम राज्य

191

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

ए. एन. आर., ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 710; एलतेमेश रेन बनाम भारत संघ और अन्य, ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 1768; भारत संघ बनाम श्री गजानन महाराज संस्थान, (2002) 5 एस. सी. सी. 44; और कॉमन कॉज बनाम भारत संघ और अन्य, ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 4493, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केंद्र सरकार को उस क़ानून में संसद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी क़ानून में एक क़ानून या प्रावधान को लागू करने का निर्देश देने वाली अनिवार्य प्रकृति की रिट जारी नहीं की जा सकती है। ”

(49) तदनुसार, प्रश्न संख्या 2 का निर्णय भी याचिकाकर्ताओं के पक्ष में और राज्य के खिलाफ किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर जो है (यदि प्रश्न संख्या 2 का उत्तर किसी भी तरह से दिया जाता है, तो क्या राज्य निजी नियोक्ताओं को ऐसा करने के लिए एक कानून प्रदान कर सकता है जो भारत के संविधान के तहत उसके लिए निषिद्ध था?)

(50) बचाव में, श्री पुनीत बाली ने डी. पी.

27 1955 (1) एससीआर 1215

28 1995 (4) एस. सी. सी. 520 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

192

मुद्दा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में किए गए संशोधन और अधिवास की आवश्यकता को हटाने के तथ्य के बारे में था। रिलायंस को राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम भारत संघ 30 के फैसले पर भी रखा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि "किसी भी मामले" को "प्रत्येक मामले" के रूप में नहीं माना जा सकता है और संवैधानिक प्रावधानों की जांच करते समय न्यायालयों को इसकी व्याख्या करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था और जो व्याख्या ध्यान में रखी जानी थी वह यह थी कि न्यायालय का काम यह था कि भाषा की व्याख्या संविधान के उद्देश्य की सर्वोत्तम पूर्ति के रूप में की जाए। (52) भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (डी), 19 (1) (ई) और 19 (1) (जी) इस प्रकार हैंः -

(a), (b) और (c) XXX (घ) भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना; (छ) किसी भी पेशे का अभ्यास करना, या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को जारी रखना। ”

(53) भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (5) और 19 (6) इस प्रकार हैंः -

“19(5) उक्त खंड के उपखंड (घ) और (ङ) की कोई भी बात किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, जहां तक वह अधिरोपित करती है, या राज्य को उक्त उपखंडों द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने से रोकती है।

29 2006 (7) एससीसी 1

30 2018 ( 8) एस. सी. सी. 501 आई. एम. टी. औद्योगिक संघ और ए. एन. डी. आर. बनाम राज्य

193

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

(i) किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक पेशेवर या तकनीकी योग्यता, या ((ख) नागरिकों के किसी भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को, चाहे वह पूर्ण रूप से हो या आंशिक रूप से, राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व वाले या नियंत्रित निगम द्वारा चलाया जाना। ”

(54) तदनुसार, एम. नागराज और अन्य बनाम यू. ओ. आई. और अन्य 31 का उल्लेख करते हुए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बदलती स्थितियों का अनुमान लगाने और उन्हें ध्यान में रखने के उद्देश्यों के लिए संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा के मानकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि संविधान स्वयं लचीला था और जीवाश्म नहीं था। इन सिद्धांतों को संविधान को सुसंगत बनाने और इसे एक जैविक समग्र बनाने के लिए निर्धारित किया गया था, भले ही यह स्पष्ट रूप से लिखित रूप में नहीं कहा गया था और हालांकि स्पष्ट रूप से संरचित नहीं था। यह सही तर्क दिया गया था कि यह सभी अधिनियमित कानूनों में व्याप्त होगा और संवैधानिक मूल्यों के पदानुक्रम के शिखर पर खड़ा होगा। स्वयं संविधान का उपयोग कानूनी रूप से खुद को नष्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता था क्योंकि राज्य इस राष्ट्र की बहुमूल्य विरासत को नष्ट करने का प्रयास कर रहा था और भारत के संविधान की पहचान की रक्षा की जानी चाहिए। संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांतों को लागू करते समय अखंडता पर इसके इनकार के परिणामों को ध्यान में रखना था। इन टिप्पणियों पर जोर दिया जा सकता है कि भारत में लोकतंत्र केवल "भारतीय धरती पर एक शीर्ष परिधान है जो अनिवार्य रूप से अलोकतांत्रिक है" और यह डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा किया गया अवलोकन था जब संविधान बनाया गया था और उक्त सिद्धांत को अभी भी ध्यान में रखना होगा। रिलायंस को तदनुसार शीर्ष 31 2006 (8) एस. सी. सी. 212 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा के फैसले पर रखा जा सकता है।

2024(1)

194

(55) भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने भी उसी फैसले में संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत को विस्तार से बताते हुए कहा था कि लोकतंत्र सरकारों के चुनाव तक ही सीमित नहीं है, जबकि फिर से डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा था। इस प्रकार, संविधान के नैतिक मूल्यों को हर स्तर पर बनाए रखा जाना चाहिए और यह केवल संविधान का पाठ नहीं है जो इसकी रक्षा कर सकता है। बहुमत के अत्याचार और भीड़ शासन के उदय के खिलाफ टिप्पणियों को संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत द्वारा संतुलित किया जाना चाहिए और जो उनके खिलाफ एक सीमा के रूप में कार्य करना है, कुछ टिप्पणियां थीं जो की गई थीं और यह वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुरूप होगी। इस देश के नागरिकों के बीच उनके अधिवास और राज्य से संबंधित होने के कारण अंतर करने का प्रयास किया जा रहा है।

32 2014 (9) एस. सी. सी. 1 आई. एम. टी. औद्योगिक संघ और ए. एन. डी. आर. बनाम राज्य

195

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

“प्रभावी होने के लिए, संवैधानिक कानूनों को संवैधानिक नैतिकता के आधार पर टिका होना चाहिए। संवैधानिक नैतिकता के अभाव में, संविधान का संचालन, चाहे कितना भी सावधानी से लिखा गया हो, मनमाना, अनियमित और मनमौजी हो जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून के क्षेत्र को राजनीति से पूरी तरह से अलग करना संभव नहीं है। हमारे जैसे संविधान से अपेक्षा की जाती है कि वह इस बारे में मार्गदर्शन प्रदान करे कि कानून के अवैयक्तिक शासन द्वारा क्या विनियमित किया जाना चाहिए और दलों के बीच, गुटों के बीच और राजनीतिक नेताओं के बीच सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा से क्या तय किया जा सकता है। यहीं पर संवैधानिक नैतिकता का महत्व निहित है। विधायकों, न्यायाधीशों, वकीलों, मंत्रियों, सिविल सेवकों, लेखकों और सार्वजनिक बुद्धिजीवियों के बीच संवैधानिक नैतिकता के कुछ मिश्रण के बिना, संविधान शक्ति दलालों का एक खेल बन जाता है। ” (56) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में दिए गए संबोधन का उल्लेख इस बात पर टिप्पणी करने के लिए किया जा सकता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन यह बुरा साबित हो सकता है यदि जिन लोगों को इस पर काम करने का मौका मिलता है वे बहुत खराब होते हैं। इस प्रकार, भारत के संविधान की व्याख्या वास्तविक पाठ पर नहीं है, बल्कि अंतर्निहित समझ पर है और इस प्रकार, यह उस पर आधारित है जो अप्रकाशित था। पैरा राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) मामले (उपरोक्त) की संख्या 301 और 302 इस प्रकार हैः -

“ 301. संवैधानिक नैतिकता के लिए संविधान की भावना को बढ़ाने और पूर्ण करने के लिए संवैधानिक मौन को भरने की आवश्यकता होती है। संविधान सरकार की संरचना स्थापित कर सकता है, लेकिन ये संरचनाएं कैसे काम करती हैं, यह संवैधानिक मूल्यों के आधार पर निर्भर करता है। संवैधानिक नैतिकता का उद्देश्य संवैधानिक विवादों को निपटाने के लिए एक मार्गदर्शक आधार के रूप में कार्य करके अतीत को राष्ट्र की आत्मा को फाड़ने से रोकना हैः “अनिवार्य रूप से संविधान अधूरे हैं। पाठ में जो स्पष्ट है वह अंतर्निहित समझ पर निर्भर करता है; जो कहा गया है वह उस पर निर्भर करता है जो अव्यक्त है। ”

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

196

302. संवैधानिक नैतिकता शासन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक सैद्धांतिक समझ प्रदान करती है। यह अशांत जल में पकड़ने के लिए एक कम्पास है। यह संस्थानों के जीवित रहने के लिए मानदंडों और व्यवहार की अपेक्षा को निर्दिष्ट करता है जो न केवल पाठ बल्कि संविधान की आत्मा को पूरा करेगा। हमारी अपेक्षाएँ वास्तविकता से बहुत आगे हो सकती हैं। लेकिन उस दस्तावेज़ के मूल्यों से प्राप्त संवैधानिक नैतिकता की भावना हमें अपने संस्थानों और अपने भाग्य की अध्यक्षता करने वालों को जिम्मेदार ठहराने में सक्षम बनाती है। इसलिए, संवैधानिक व्याख्या संवैधानिक नैतिकता से आनी चाहिए। ”

(57) इस प्रकार, वकील ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत शक्ति का प्रयोग भी संवैधानिक नैतिकता के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उद्देश्य और जिम्मेदारी की भावना में होना चाहिए और यह कि राजनेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संस्थापक पिताओं का मूल्य बना रहे और संविधान को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे लोकतांत्रिक शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में शामिल किया गया था।

(58) नवतेज में संविधान पीठ द्वारा की गई टिप्पणियां

सिंह जौहर और अन्य बनाम भारत संघ 33 का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें यह आई. पी. सी. की धारा 377 के प्रावधानों और प्रत्येक नागरिक को गरिमा और निजता के अधिकार के साथ रहने के लिए दी गई पहचान से संबंधित है, जब तक कि वे समान लिंग के वयस्कों की सहमति लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में एलजीबीटी व्यक्तियों के अधिकार को बरकरार रखा गया था। ऐसी परिस्थितियों में, सर्वोच्च न्यायालय ने राय दी थी कि समान अधिकार रखने वाले छोटे अल्पसंख्यकों को दरकिनार किया जा रहा है और उन्हें एक नागरिक के रूप में भाग लेने का अधिकार है और जीवन के आनंद का समान अधिकार है, भले ही बहुमत चाहे जो भी माने और केवल तभी संविधान के मूलभूत वादों को पूरा किया जा सकता है। वर्तमान कानून बनाते समय राज्य द्वारा उक्त सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, जिस पर हमला हो रहा है, जबकि भारत के बाकी नागरिकों को प्रवासी कहा जा रहा है। इस प्रकार भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की टिप्पणियों पर फिर से भरोसा किया जा सकता है कि यह राज्य की जिम्मेदारी थी कि वह लोकप्रिय भावना या बहुसंख्यकवाद की किसी भी प्रवृत्ति या प्रवृत्ति पर अंकुश लगाए और यह तर्क दे कि लोकप्रिय भावना देश के नागरिकों के अधिकारों पर हावी नहीं हो सकती और न ही स्थानीय प्रांतीय हित को बढ़ावा दे सकती है जो अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों से स्पष्ट है। इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रता को 33 2018 (10) एस. सी. सी. 1 आई. एम. टी. औद्योगिक संघ और ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए. एन. ए

197

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

(59) साझा भाईचारे की भावना को दर्शाने वाला शब्द बंधुत्व सभी भारतीयों को गले लगाना है और देश के अन्य नागरिकों की ओर आंखें मूंद कर नहीं रखा जा सकता, चाहे वे किसी भी राज्य के हों। इसलिए, हरियाणा के गैर-निवासियों, जिन्हें द्वितीयक नागरिक के रूप में नहीं माना जा सकता था, उनकी ओर आंखें मूंदते हुए भारत के संविधान के मूलभूत वादों के खिलाफ इस क़ानून के माध्यम से एक विधायी आदेश लागू नहीं किया जा सका, जैसा कि किया जा रहा था। इस प्रकार, राज्य एक दूरदर्शी दृष्टि के साथ कार्य कर रहा था और इस प्रकार यह क़ानून सर्वोच्च न्यायालय और स्वयं संविधान के संवैधानिक निर्णयों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों की अवहेलना करने के लिए उत्तरदायी है। हरियाणा राज्य से संबंधित नागरिकों के एक समूह को द्वितीयक दर्जा देकर और अपनी आजीविका कमाने के लिए उनके मौलिक अधिकारों में कटौती करके संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा का खुले तौर पर उल्लंघन किया गया है। राज्यों को उक्त प्रतिबंधों से बाहर रखते हुए विधायी आदेश के माध्यम से निजी रोजगार पर प्रतिबंध के दोहन और उसके उल्लंघन के कारण नियोक्ता को अपराधीकरण के दायरे में रखने को असंवैधानिक कहा जा सकता है क्योंकि एक निजी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए नहीं कहा जा सकता है जो राज्य को अपने लिए निषिद्ध किया गया है। (60) यह ध्यान देने योग्य है कि अमेरिका के संविधान ने अपने पांचवें संशोधन के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी भी नागरिक को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, जबकि चौदहवें संशोधन के तहत, उन नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की जाती है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और उन सभी राज्यों में पैदा हुए हैं या प्राकृतिक हैं जहां वे रहते हैं। राज्य को ऐसा कोई भी कानून बनाने या लागू करने से रोक दिया गया है जो देश के नागरिक के रूप में उनके विशेषाधिकारों को कम करेगा और न ही उन्हें उचित प्रक्रिया के बिना उनकी स्वतंत्रता, संपत्ति से वंचित किया जा सकता है और न ही इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले व्यक्ति को कानूनों के समान संरक्षण से वंचित किया जा सकता है। हमारे संविधान के उक्त संविधान के सिद्धांतों से बहुत अधिक उधार लेने का तथ्य सर्वविदित है और इसलिए, यू. एस. के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा में दिया जा सकता है।

2024(1)

198

जेम्स रिचर्ड पीटरसन बनाम सिटी ऑफ ग्रीनविल 34। तदनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वारेन ने अभिनिर्धारित किया कि यदि राज्य स्वयं विशेष परिणाम का आदेश देता है और व्यक्तियों को भेदभाव करने के लिए मजबूर करता है, तो यह XIVth संशोधन का स्पष्ट उल्लंघन होगा। ये टिप्पणियां इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आई थीं कि त्वचा के रंग के कारण व्यक्तियों को एक रेस्तरां में परोसा नहीं गया था क्योंकि एक ही कमरे में सफेद और रंगीन व्यक्तियों को भोजन देने के लिए एक बार था जो एक अध्यादेश के माध्यम से था। ऐसी परिस्थितियों में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईंः -

एस. सी. 865; टर्नर बनाम मेम्फिस, 369 यू. एस. 350,82 एस. 805, 7 एल. एड. 2डी 762। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यहां राज्य की एक एजेंसी, ग्रीनविल शहर ने अपने अध्यादेश के माध्यम से यह प्रावधान किया है कि एक रेस्तरां सुविधा को अलग-अलग आधार पर संचालित किया जाना है या नहीं, इसका निर्णय उसके लिए आरक्षित है। जब राज्य ने किसी विशेष परिणाम का आदेश दिया है, तो उसने उस परिणाम को निर्धारित करने की शक्ति को अपने लिए बचा लिया है और इस तरह "काफी हद तक" इसमें "शामिल" हो गया है, और वास्तव में, उस निर्णय को निजी पसंद के क्षेत्र से हटा दिया है। इस प्रकार यह प्रभावी रूप से निर्धारित किया गया है कि एक भोजन स्थल के मालिक, प्रबंधन या नियंत्रण करने वाले व्यक्ति के पास अपना कोई विकल्प नहीं बचा है, लेकिन उसे अपने श्वेत और नीग्रो संरक्षकों को अलग करना होगा। क्रेस प्रबंधन ने नीग्रों को बाहर करने का निर्णय लेते हुए ठीक वही किया जो शहर के कानून के लिए आवश्यक था। नतीजतन ये विश्वास खड़े नहीं हो सकते हैं, यहां तक कि यह मानते हुए भी, जैसा कि प्रतिवादी का तर्क है, कि प्रबंधक ने स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से काम किया होगा

34 1963 (373) यू. एस. 244 आई. एम. टी. औद्योगिक संघ और ए. एन. डी. आर. बनाम राज्य

199

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

अध्यादेश। राज्य को दोषसिद्धि के समर्थन में यह तर्क देते हुए नहीं सुना जाएगा। इन दोषसिद्धि का प्रभाव राज्य की एजेंसी ग्रीनविल शहर द्वारा पारित अध्यादेश को लागू करने पर पड़ा, जिससे राज्य इनकार नहीं कर सकता। जब कोई राज्य एजेंसी एक कानून पारित करती है जो व्यक्तियों को नस्ल के कारण अन्य व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने के लिए मजबूर करती है, और राज्य की आपराधिक प्रक्रियाओं को इस तरह से नियोजित किया जाता है जो उस कानून द्वारा अनिवार्य भेदभाव को लागू करता है, तो चौदहवें संशोधन के इस तरह के स्पष्ट उल्लंघन को भेदभाव करने वालों की मानसिक इच्छाओं को अलग करने का प्रयास करके नहीं बचाया जा सकता है। उल्टा हुआ। ”

(61) इसी तरह, सैंड्रा एडिकेस बनाम में। एस. एच. क्रेस और

कंपनी 35, एक श्वेत शिक्षिका और उसके छह छात्र, जो श्वेत नहीं थे, को एक विशेष रेस्तरां में दोपहर के भोजन के लिए जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें रंगीन त्वचा वाले व्यक्तियों की कंपनी में होने के कारण सेवा से इनकार कर दिया गया था, जो कि मिसिसिपी आपराधिक ट्रेसपास क़ानून के तहत राज्य द्वारा लागू एक प्रथा थी। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय फिर से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि कोई कानून XIVth संशोधन का उल्लंघन करता है, तो उसे अमान्य घोषित किया जा सकता है और न तो राज्य इस तरह के कानून को लागू कर सकता है और न ही इस तरह के किसी विशेष परिणाम का आदेश दे सकता है। उपरोक्त निर्णय में न्यायमूर्ति हार्लन की प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैंः -

“बी. राज्य अधिनियम 14वां संशोधन विवाद [15] याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत की मूल गणना की वसूली करने के लिए, उसे चौदहवें संशोधन के समान संरक्षण खंड द्वारा गारंटीकृत अधिकार से वंचित होना चाहिए। चूँकि "चौदहवें संशोधन की पहली धारा द्वारा बाधित कार्रवाई केवल ऐसी कार्रवाई है जिसे उचित रूप से राज्यों की कार्रवाई कहा जा सकता है", शेली बनाम क्रेमर, 334 यू. एस. 1,13,92 एल. एड. 1161, 1180, 68 एस. सी. टी. 836,3 ए. एल. आर. 2 डी. 441 (1948), हमें इस मामले की खरीद मुद्राओं के लिए, निम्नलिखित "राज्य कार्रवाई" मुद्दे पर निर्णय लेना चाहिएः क्या याचिकाकर्ता के चौदहवें संशोधन अधिकारों के उल्लंघन को साबित करने के लिए पर्याप्त राज्य कार्रवाई है यदि वह दिखाती है कि क्रेस ने हैटिज़बर्ग रेस्तरां में दौड़ के राज्य-लागू प्रथा मजबूर अलगाव के कारण अपनी सेवा से इनकार कर दिया था?

35 1970 (398) यूएस 144 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

200

[17] इन दो चरम सीमाओं के बीच किस बिंदु पर इनकार में एक राज्य की भागीदारी चौदहवें संशोधन का उल्लंघन करने के लिए निजी इनकार करने के लिए पर्याप्त हो जाती है, यह हमारे मामले के कानून के तहत स्पष्ट नहीं है। यदि किसी राज्य में कोई कानून था जिसमें किसी निजी व्यक्ति को नस्ल के कारण सेवा से इनकार करने की आवश्यकता होती है, तो यह विवाद से परे स्पष्ट है कि कानून चौदहवें संशोधन का उल्लंघन करेगा और इसे अमान्य घोषित किया जा सकता है और प्रवर्तन से आदेश दिया जा सकता है। न ही कोई राज्य ऐसे कानून को लागू कर सकता है जिसमें भेदभाव करने से इनकार करने वाले मालिकों की दोषसिद्धि के माध्यम से भेदभाव की आवश्यकता होती है, या संरक्षकों पर अतिचार मुकदमा चलाया जा सकता है, जो इस तरह के कानून के अनुसार सेवा से वंचित होने के बाद, परिसर छोड़ने के अनुरोध का सम्मान करने से इनकार करते हैं। हालाँकि, इस मामले के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक प्रश्न थोड़ा अलग है। यह है कि क्या किसी रेस्तरां के मालिक का राज्य के कानून की मजबूरी के तहत नस्ल के आधार पर भेदभाव करने का निर्णय चौदहवें संशोधन का उल्लंघन करता है। यद्यपि इस न्यायालय ने इस प्रश्न में निहित चौदहवें संशोधन राज्य कार्रवाई के मुद्दे पर स्पष्ट रूप से निर्णय नहीं लिया है, लेकिन धरना देने वाले मामलों में न्यायालय के निर्णयों में अंतर्निहित यह धारणा है कि एक राज्य एक निजी पक्ष के भेदभावपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदार है जब राज्य ने अपने कानून द्वारा अधिनियम को मजबूर किया है। जैसा कि न्यायालय ने पीटरसन बनाम सिटी ऑफ ग्रीनविल, 373 यू. एस. 244,248,10 एल. एड. में कहा। 2डी 323,326,83 एस. सी. टी. 1119 (1963): "जब राज्य ने किसी विशेष परिणाम का आदेश दिया है, तो उसने उस परिणाम को निर्धारित करने की शक्ति को अपने लिए बचा लिया है और इस तरह 'काफी हद तक' आई. एम. टी. औद्योगिक संघ और अन्य बनाम राज्य का राज्य है।

201

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

बाल्डविन बनाम मॉर्गन, ऊपर, पाँचवें सर्किट में कहा गया है कि "इन राज्य आदेशों के अनुसार [रेल] टर्मिनल द्वारा किए जाने पर अलग [प्रतीक्षा कक्ष] सुविधाओं को तैनात करने और बनाए रखने का कार्य राज्य द्वारा कार्रवाई है।" इसके बाद अदालत ने कहाः "जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि राज्य भेद के आधार के रूप में नस्ल या रंग का उपयोग नहीं कर सकता है। यह प्रत्यक्ष कार्रवाई या अन्य लोगों के माध्यम से ऐसा नहीं कर सकता है जो ऐसा करने के लिए राज्य की मजबूरी में हैं। आईडी., 755-756 पर (जोर जोड़ा गया)। हम सोचते हैं कि वही सिद्धांत यहाँ शासन करता है। [18] राज्य कार्रवाई के उद्देश्यों के लिए यह निश्चित रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या निजी पक्ष द्वारा नस्लीय भेदभावपूर्ण कार्य एक वैधानिक प्रावधान द्वारा या कानून के बल वाली प्रथा द्वारा मजबूर किया जाता है-किसी भी मामले में यह राज्य है जिसने अपने कानून द्वारा परिणाम की कमान संभाली है। यह तय किए बिना कि क्या किसी राज्य की कम महत्वपूर्ण भागीदारी चौदहवें संशोधन की राज्य कार्रवाई की आवश्यकता को पूरा कर सकती है, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि याचिकाकर्ता अपने समान सुरक्षा अधिकार को कम करेगी, अगर वह यह साबित करती है कि क्रेस ने सार्वजनिक रेस्तरां में दौड़ को अलग करने की राज्य द्वारा लागू प्रथा के कारण अपनी सेवा से इनकार कर दिया था। ”

(62) न्यायमूर्ति ब्रेनन की टिप्पणियों का भी यही प्रभाव था कि अलगाव की राज्य नीति के आधार पर रेस्तरां का अलगाव असंवैधानिक राज्य कार्रवाई थी। प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः - “राज्य-कार्रवाई सिद्धांत इस गहन निर्णय को दर्शाता है कि समान व्यवहार से इनकार, और विशेष रूप से नस्ल या रंग के कारण इनकार, अकेले गंभीर होते हैं जब सरकार के पास उनके लिए जिम्मेदारी होती है या साझा होती है। सरकार एक ऐसा सामाजिक अंग है जिसके लिए हमारे समाज में सभी लोग स्वतंत्रता, न्याय, निष्पक्ष और समान व्यवहार को बढ़ावा देने और सामाजिक आचरण के लिए योग्य मानदंडों और लक्ष्यों की स्थापना की तलाश करते हैं। इसलिए, एक ऐसे समाज में कुछ विशिष्ट रूप से गलत है जहां सरकार, सामुदायिक मूल्यों का आधिकारिक दैवज्ञ, नस्लीय भेदभाव में खुद को शामिल करती है। तदनुसार, हमारे समक्ष आए मामलों में इस न्यायालय ने नस्लीय आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा में राज्य की महत्वपूर्ण भागीदारी की निंदा की है।

2024(1)

202

"नतीजतन, ये विश्वास कायम नहीं रह सकते हैं, यह मानते हुए भी, जैसा कि प्रतिवादी तर्क देता है, कि आदमी ने अध्यादेश के अस्तित्व से स्वतंत्र रूप से काम किया होगा। 373 यूएस, 248,10 एल एड 2 डी 326 पर। हालाँकि इस मामले में अतिचार के दोषसिद्धि शामिल थी, लेकिन न्यायालय ने राज्य की कार्रवाई के तत्वों का विश्लेषण करने में अपने तटस्थ अतिचार कानूनों के राज्य के प्रवर्तन पर भरोसा नहीं किया। न ही इसने शेली बनाम क्रेमर, ऊपर, न्यायिक प्रवर्तन के संदर्भ में विश्लेषण के लिए तार्किक प्रारंभिक बिंदु का हवाला दिया। समान सुरक्षा से इनकार तब हुआ जब याचिकाकर्ताओं को रेस्तरां में सेवा से वंचित कर दिया गया।

वह आई. एम. टी. औद्योगिक संघ और एक अन्य बनाम राज्य

203

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

समान संरक्षण से इनकार ने बाद के दोषसिद्धि को कलंकित कर दिया। और जैसा कि रीटमैन बनाम मुल्की, 387 यू. एस. 369,380,181 में उल्लेख किया गया था। एड 2डी 830,837,87 एस. सी. टी. 1627 (1967) में, "इस बात के प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी कि रेस्तरां का मालिक वास्तव में राज्य के क़ानून से प्रभावित था।" इस प्रकार पीटरसन इस प्रस्ताव को स्थापित करता है कि जहां एक राज्य व्यक्तियों के एक वर्ग को नस्ल के आधार पर भेदभाव करने का आदेश देता है, उस वर्ग के भीतर एक निजी व्यक्ति द्वारा भेदभाव राज्य की कार्रवाई है, भले ही वह आदेश से प्रेरित हो। वर्तमान मामले में न्यायालय की यह सूचना कि निजी भेदभाव केवल राज्य की कार्रवाई हो सकती है, जहां निजी व्यक्ति ने राज्य द्वारा लगाई गई मजबूरी के तहत काम किया हो, पीटरसन में श्री न्यायमूर्ति हार्लन के इस तर्क को प्रतिध्वनित करता है कि निजी भेदभाव केवल राज्य की कार्रवाई है जहां राज्य निजी व्यक्ति को भेदभाव करने के लिए प्रेरित करता है। 373 यूएस, 251-253 पर, 10 L Ed 2d 328-329 पर देखें। पीटरसन के मामले में अदालत ने उस तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया था, और मुझे अब इसे पुनर्जीवित करने का कोई कारण नहीं दिखता है। ”

(63) संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में पांचवें और चौदहवें संशोधन भी इस प्रकार हैंः -

“ए. एम. डी. एम. एन. टी. वी.

“किसी भी व्यक्ति को राजधानी या अन्यथा कुख्यात अपराध के लिए जवाब देने के लिए नहीं रखा जाएगा, जब तक कि युद्ध या सार्वजनिक खतरे के समय वास्तविक सेवा में होने पर भूमि या नौसेना बलों या मिलिशिया में उत्पन्न होने वाले मामलों को छोड़कर, ग्रैंड जूरी के अभियोग की प्रस्तुति पर; न ही कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए दो बार जीवन या अंग के खतरे में डाला जाएगा; न ही किसी आपराधिक मामले में अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर किया जाएगा, न ही कानून की उचित प्रक्रिया के बिना जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित किया जाएगा; न ही निजी संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए लिया जाएगा, बिना उचित मुआवजे के। ”

“ए. एम. डी. एम. एन. टी. XIV

13 जून, 1866 को कांग्रेस द्वारा पारित किया गया, 9 जुलाई, 1868 को अनुमोदित किया गया। ध्यान देंः संविधान के अनुच्छेद I, धारा II को चौदहवें संशोधन की धारा II द्वारा संशोधित किया गया था।

खंड I

संयुक्त राज्य अमेरिका, आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा में पैदा हुए या प्राकृतिककृत सभी व्यक्ति

2024(1)

204

और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और उस राज्य के नागरिक हैं जहाँ वे रहते हैं। कोई भी राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा या लागू नहीं करेगा जो संयुक्त राज्य के नागरिकों के विशेषाधिकारों या उन्मुक्ति को कम करेगा और न ही कोई राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित करेगा और न ही अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानूनों के समान संरक्षण से वंचित करेगा। ”

(66) परिणामस्वरूप, हम प्रश्न संख्या 3 का उत्तर राज्य के विरुद्ध और याचिकाकर्ताओं के पक्ष में भी देते हैं। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर, जो है (क्या विधान आम जनता के हित में उचित प्रतिबंध प्रदान करता है और इस प्रकार आई. एम. टी. औद्योगिक संघ के अनुच्छेद 19 (5) और 19 (6) के तहत राज्य को अधिकार देता है और अन्य बनाम राज्य का राज्य।

205

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

उसी को सही ठहराने के लिए भारत का संविधान?) (67) श्री बाली, जैसा कि ऊपर देखा गया है, ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (5) और 19 (6) का उल्लेख किया है कि यह आम जनता के हित में था कि राज्य ऐसा कर रहा था और इसलिए, यह उसके अधिकार के भीतर था और केवल उचित प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और 25 प्रतिशत अकुशल कार्यबल अभी भी देश के बाकी हिस्सों से आ सकता है। (68) याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने तर्क दिया है कि 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का उद्देश्य भेदभावपूर्ण है और कोई उचित वर्गीकरण नहीं है और क़ानून को छोड़ देना चाहिए। नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और एक अन्य बनाम विट्ठल राव और अन्य 36 के फैसले पर रिलायंस को सही रखा गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की पीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए भूमि अधिग्रहण के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों पर विचार किया है। नागपुर सुधार न्यास अधिनियम, 1936 के तहत भूमि अधिग्रहण को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि कीमतें उन कीमतों से कम थीं जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहण किए जाने पर देय होतीं। तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया गया कि मुआवजे के सार्वजनिक उद्देश्य के आधार, जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है, को उचित वर्गीकरण नहीं माना जा सकता है और इसे टिकाऊ नहीं माना गया है। संबंधित अनुच्छेद इस प्रकार हैंः -

“26. किस भूमि के लिए अधिग्रहित मुआवजे के उद्देश्य से सार्वजनिक उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है? दूसरे शब्दों में, क्या विधायिका अधिग्रहित भूमि जैसे अस्पताल या स्कूल या सरकारी भवन के लिए मुआवजे के विभिन्न सिद्धांतों को निर्धारित कर सकती है? क्या विधायिका यह कह सकती है कि अस्पताल के लिए बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत पर स्कूल के लिए 60 प्रतिशत पर और सरकारी भवन के लिए बाजार मूल्य के 70 प्रतिशत पर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा? तीनों उद्देश्य सार्वजनिक उद्देश्य हैं और जहां तक मालिक का संबंध है, उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक सार्वजनिक उद्देश्य है या अन्य अनुच्छेद 14 एक व्यक्तिगत अधिकार प्रदान करता है और एक वर्गीकरण को उचित ठहराने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो इस व्यक्तिगत अधिकार के साथ एक अलग व्यवहार को उचित ठहराता है। हमें ऐसा लगता है कि क्षतिपूर्ति निर्धारित करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 14 के तहत आम तौर पर सार्वजनिक उद्देश्य पर आधारित वर्गीकरण की अनुमति नहीं है। स्थिति अलग होती है जब मालिक

36 1973 (1) एस. सी. सी. 500 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

206

भूमि स्वयं एक सुधार योजना से लाभ प्राप्त करने वाली है, और उसे मिलने वाले लाभ को मुआवजे के निर्धारण में ध्यान में रखा जाता है। क्या भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है? दूसरे शब्दों में, क्या मुआवजे के सिद्धांत अलग-अलग हो सकते हैं यदि भूमि का अधिग्रहण किसी सुधार न्यास या नगर निगम या सरकार के लिए या उसके द्वारा किया जाता है? हमें ऐसा लगता है कि इसका उत्तर नकारात्मक है क्योंकि जहां तक मालिक का संबंध है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भूमि एक प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई है या दूसरे द्वारा। 27. चाहे वह एक अधिग्रहण अधिनियम हो या कोई अन्य अधिग्रहण अधिनियम जिसके तहत भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है। यदि दो अधिनियमों का अस्तित्व राज्य को एक मालिक को दूसरे से अलग व्यवहार देने में सक्षम बनाता है, तो समान रूप से स्थित मालिक, जिसके साथ भेदभाव किया जाता है, अनुच्छेद 14 के संरक्षण का दावा कर सकता है। 28. यह कहा जाता था कि यदि यह सही स्थिति है तो राज्य के लिए झुग्गियों को साफ करना, कई अन्य प्रशंसनीय कार्य करना असंभव होगा। यदि इस तर्क को स्वीकार किया जाता है तो यह अनुच्छेद 14 द्वारा दिए गए संरक्षण के लिए पूरी तरह से विनाशकारी होगा। यह राज्य को अस्पताल के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए एक कानून, स्कूलों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए एक कानून, झुग्गियों को साफ करने के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए एक कानून, सरकारी भवनों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए एक कानून बनाने में सक्षम बनाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा ही है, लेकिन अनुच्छेद 14 अपने पड़ोसी को अछूता छोड़ते हुए एक मालिक की अनर्जित वृद्धि को जब्त करने पर प्रतिबंध लगाता है। यह पड़ोसी अपनी भूमि बेच सकता है और अनर्जित increment.If काट सकता है, इस कानून का उद्देश्य अनर्जित वृद्धि पर कर लगाना है और यह पूरे राज्य में किया जाना चाहिए। राज्य दूसरों को अकेला छोड़कर कुछ मालिकों की भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण करके इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि उद्देश्य झुग्गियों को साफ करना है तो यह उन मालिकों की कीमत पर नहीं किया जा सकता है जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जब तक कि जैसा कि हमने कहा है कि मालिक को योजना से सीधे लाभ नहीं होता है। यदि उद्देश्य अस्पतालों का निर्माण करना है तो यह अधिग्रहित भूमि के मालिकों की कीमत पर नहीं किया जा सकता है। अस्पताल, स्कूल आदि का निर्माण पूरे समुदाय के खर्च पर किया जाना चाहिए। ”

(69) श्री बाली द्वारा प्रस्तावित उचित प्रतिबंधों से औद्योगिक संघ और अन्य बनाम राज्य का प्रभाव बढ़ेगा।

207

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

38 1978 (1) एस. सी. सी. 248

39 1980 (3) एस. सी. सी. 625 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

208

आम जनता का हित जो राज्य को कोई कानून बनाने या किसी अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण के लिए अनुमति दे सकता है। इसलिए, यह अधिनियम भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने या भारत के किसी भी हिस्से या क्षेत्र में रहने और बसने के अधिकार के संबंध में अनुचित प्रतिबंध लगा रहा है। इसी तरह, अनुच्छेद 19 (6) का उल्लेख करते हुए, यह कहा जा सकता है कि राज्य का अधिकार अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक अस्थायी या तकनीकी योग्यताओं के बारे में है या अन्य नागरिकों को छोड़कर राज्य या उसके निगमों द्वारा विशेष रूप से किसी भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को जारी रखने का अधिकार है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इस अधिनियम को किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता है और यह नियोक्ताओं को संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने का निर्देश दे रहा था।

(72) पी. ए. इनामदार में निर्णय पर भरोसा रखा जा सकता है

(73) अनुच्छेद 2 (ई) के तहत परिभाषित सभी प्रकार के निजी नियोक्ताओं पर लगाए गए प्रतिबंध इस हद तक सकल हैं कि किसी व्यक्ति का व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार सकल रूप से 40 2005 (6) एससीसी 537 है।

41 2014 (8) एस. सी. सी. 1 आई. एम. टी. औद्योगिक संघ और ए. एन. डी. आर. बनाम राज्य

209

हरियाणा और एक और (जी. एस. संधवालिया, जे.)

रिट याचिकाओं को अनुमति दी जा सकती है और हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम, 2020 को असंवैधानिक और भारत के संविधान के भाग III का उल्लंघन करने वाला माना जाता है और तदनुसार इसे इसके विपरीत माना जाता है और यह लागू होने की तारीख से अप्रभावी है। रिपोर्टर-कृति शर्मा अवस्थी